घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 29- शनिवार 29- नवम्बर 2025,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये ,www.ghatati-ghatana.com,RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2023-2025

प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण

लोगों की एकता से होकर जाती है विकसित भारत की राह : मोदी

कैनाकोना,28 नवम्बर 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गोवा जिले के श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ में पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री मठ के 550वें साल के जश्न 'सार्ध पंचशतामनोत्सव' के मौके पर मठ आए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रामायण थीम पार्क गार्डन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने एक विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा में कहा कि विकसित भारत का रास्ता लोगों की एकता से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि आज देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है और अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और उज्जैन महाकाल महालोक इसका उदाहरण हैं।

बदलते समय और चुनौती के बीच मठ ने नहीं खोई अपनी दिशा : पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, यहां भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य की मूर्ति स्थापित की गई। तीन दिन पहले मुझे अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वज फहराने का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने कहा कि बदलते समय और चुनौतियों के बीच भी इस मठ ने अपनी दिशा नहीं खोई। बल्कि यह 'मठ' लोगों को दिशा देने वाला सेंटर बनकर उभरा। यही इसकी पहचान है। यह मठ समय के साथ बदलता रहा है।

सेवा की भावना है मठ की खासियत : पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा,यह मठ मूल्यों को बनाए रखने की नींव का पत्थर रहा है,और आने वाली पीढ़ियों को ऊर्जा देता रहेगा...इस मठ की एक खासियत सेवा की भावना है, जिसने सदियों से समाज के हर तबके का साथ दिया है। सदियों पहले, जब इस इलाके में मुश्किलें आईं और लोगों को अपने घर-परिवार छोड़कर नई जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो इस मठ ने समुदाय का साथ दिया, नई जगहों पर मंदिर और शेल्टर बनाए। इसने न सिर्फ धर्म बल्कि इंसानियत और संस्कृति की भी रक्षा की। समय के साथ,मठ की सेवा का दायरा बढ़ा है। आज, शिक्षा से लेकर हॉस्टल तक, बुजुर्गों की देखभाल से लेकर जरूरतमंद परिवारों की मदद तक, इस मठ ने हमेशा अपने संसाधन लोगों की भलाई के लिए लगाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे समय आए जब गोवा के मंदिरों और पारंपरिक परंपराओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन घटनाओं ने समाज की भावना को कमजोर नहीं किया। गोवा की खासियत यह है कि इसकी संस्कृति ने सभी बदलावों के बावजूद अपनी एकता बनाए रखी है और समय के साथ फिर से जीवित भी हुई है। पीएम मोदी ने दक्षिणी गोवा के पार्टगली में मठ में बने मंदिर का भी दौरा किया। यह मठ भारत के सबसे पुराने मठों में से एक है, जो अपने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान के लिए जाना जाता है और सारस्वत समुदाय में इसका खास स्थान है। इस मौके पर गोवा के गवर्नर अशोक गजपति राजू और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस समारोह में मौजूद थे।

भारत की जीडीपी वृद्धि दर जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 फीसदी रही

नई दिल्ली,28 नवम्बर 2025। देश की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी है,जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि है। चालू वित्त वर्ष की (अप्रैल-जून) पहली तिमाही में यह वृद्धि दर 7.8 फीसदी थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के जारी आंकड़ों में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की (जुलाई-सितंबर) दूसरी तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी है, जो पिछली छह तिमाहियों में सर्वाधिक है। पहली तिमाही में यह 7.8 फीसदी रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में यह 5.6 फीसदी थी। एनएसओ के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगार तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। यह छह तिमाहियों में सबसे ज्यादा 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी है, जबकि पिछली तिमाही में यह 7.8 फीसदी थी। आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 14 फीसदी है, दूसरी तिमाही में 9.1 फीसदी बढ़ा है,जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में यह 2.2 फीसदी था। विनिर्माण क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 14 फीसदी का योगदान देता है। वहीं, चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत का राजकोषीय घाटा 8.25 लाख करोड़ रुपये रहा। यह वार्षिक अनुमानों का 52.6 फीसदी है। इस बार राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष के 46.5 फीसदी से अधिक है।

राष्ट्रपति ने लखनऊ में ब्रह्माकुमारी राजयोग केंद्र का किया उद्घाटन

ध्यान व योग से दूर किए जा सकता है एकाकीपन और तनाव : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

लखनऊ,28 नवम्बर 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सहारे दुनिया ने बहुत प्रगति की है, लेकिन इसके साथ ही लोगों में एकाकीपन और तनाव भी बढ़ा है। ऐसे में ब्रहमकुमारीज संस्था का शुरु किया जा रहा योग,विश्वास और एकता का अभियान लोगों को अधिक मानवीय और जीवन को आनंददायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति मुर्मु शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुलतानपुर रोड पर स्थित ब्रह्माकुमारीज राजयोग सेंटर, गुलजार उपवन में ब्रह्माकुमारीज संस्था की वार्षिक थीम 2025-26, 'विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान' के शुभारंभ करने के बाद संबोधित कर रही थीं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्था की बच्चियों ने मयूर नृत्य से राष्ट्रपति का स्वागत किया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने ओम शांति कहकर अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने ध्यान योग अभियान की शुरुआत के लिए ब्रह्मकुमारीज बहनों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में खूब तरक्की की है,लेकिन समाज में तकनीकी उन्नति के साथ एकाकीपन,ईर्ष्या, अविश्वास और दुख भी बढ़ा है। इसके लिए मेडिटेशन एक कारगर उपाय हो सकता है। ब्रहमकुमारी संस्था की कई विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति कहा कि केंद्र सरकार की ओर से महिला उत्थान, महिला सशक्तीकरण,आत्मनिर्भर भारत,ध्यान और पर्यावरण जैसे विषयों पर अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार मिशन लाइफ के माध्यम से लोगों को स्वस्थ और मानवीय बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने वर्ष 2023 में भारत में आयोजित जी-20 की थीम का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रह्मकुमारी का ध्यान और योग से जुड़ा यह अभियान मानवता को पहले से अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुख और शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर होती है और यह ध्यान और योग के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हम केवल आगे बढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं के भीतर झांकने की भी आदत डालें। विश्वास वहीं टिकता है, जहां विचार स्वस्थ और भावनाएं स्वच्छ होती हैं। हमारे भीतर आत्मिक चेतना जागृत होती है तो प्रेम, विश्वास और भाईचारा भी विकसित होता है।

मेडिटेशन से दूर होता है तनाव : आनंदीबेन पटेल

समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ब्रह्मकुमारीज संस्थान की स्थापना और उसके उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 1937 में जब समाज व्याधियों से व्यथित था, ऐसे समय में इस संस्थान की नींव रखी गई। उन्होंने कहा कि राजयोग से सुख, शांति, पवित्रता जैसे गुण स्वत: आने लगते हैं। मेडिटेशन सिखाता है कि आत्मा अमर अविनाशी है। राजयोग एक अभ्यास नहीं, बल्कि संपूर्ण सकारात्मक जीवन शैली है। वर्तमान परिस्थितियां हमारे कर्मों का ही कल है। यह अपने आप से मिलने की अनुभूति है।

महत्वपूर्ण है अभियान : योगी

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ध्यान योग को लेकर हम इतना बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति की मौजूदगी हमारे लिए गौरव की बात है। इस समारोह में आयोजक संस्था के पदाधिकारियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे।

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कराने वाला गैंगस्टर दिल्ली से गिरफ्तार

नई दिल्ली,28 नवम्बर 2025। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कनाडा में स्थित कॉमेडियन कपिल शर्मा के 'कैप्स कैफे' पर फायरिंग कराने के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इस गैंगस्टर की पहचान बंधु मान सिंह सेखों के रूप में हुई है, बंधु मान सिंह सेखों गोल्डी ढिल्लों गैंग का भारत-कनाडा बेस्ड हैंडलर बताया जा रहा है और उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच ने उसके कब्जे से हाई-एंड पीएक्स-3 पिस्टल 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

राष्ट्रपति पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत दौरे पर

नई दिल्ली,28 नवम्बर 2025। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 4 और 5 दिसंबर को भारत के स्टेट विजिट पर आने वाले हैं। रूसी सरकारी न्यूज एजेंसियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस महत्वपूर्ण दौरे में तेल आयात,रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार जैसे प्रमुख मुद्दों पर व्यापक बातचीत होने की संभावना है। पुतिन के इस दौरे की रूपरेखा अगस्त में स्पष्ट हुई थी जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को गए थे। हालांकि उस समय तारीखों की घोषणा नहीं की गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान चीन में हुई थी। विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह पुष्टि की कि पुतिन भारत और रूस के बीच 23वें सालाना समिट में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। मंत्रालय ने शुक्रवार को आधिकारिक रूप से कहा कि यह स्टेट विजिट 4 और 5 दिसंबर को आयोजित होगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु, व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में दावत का आयोजन किया जाएगा।

नीतीश सरकार ने 10 लाख महिलाओं के खाते में भेजी 10-10 हजार की राशि

पटना,28 नवम्बर 2025। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शुक्रवार को एक बार फिर बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीबीटी के माध्यम से 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की। इसके लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि जो महिलाएं बेहतर कार्य करेंगी, उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।

भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पुराने ढांचे पर भरोसा नहीं कर सकते : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली,28 नवम्बर 2025। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मानेकशा सेंटर में 'चाणक्य डिफेंस डायलॉग' के दूसरे दिन शुक्रवार को अपने समापन भाषण में तकनीकी रूप से भारत के मजबूत होने की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब भारत ताकत,सुरक्षा और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है, तो दुनिया को कई तरह से फायदा होता है। एक स्थिर भारत एक स्थिर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में योगदान देता है। हमारी आर्थिक विकास,प्रौद्योगिकीय काबिलियत और उसूलों वाली विदेशी नीति ने हमें संतुलित और जिम्मेदारी की आवाज बना दिया है। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा और कनेक्टिविटी दोनों को सहायता करने के लिए सीमा और समुद्री ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। हम नए प्लेटफॉर्म,प्रौद्योगिकी और संरचना के जरिए अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक कर रहे हैं। हम गति,पारदर्शिता और जवाबदेही पक्का करने के लिए खरीद प्रक्रिया में सुधार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के जरिए हम एक रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं,जो नवाचार को बढ़ावा देता है, उद्योगों की सहायता करता है, और बाहरी निर्भरता को कम करता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस बदलते वैश्विक माहौल में भारत की जगह भी बदल रही है। हमारी आर्थिक विकास,प्रौद्योगिकीय काबिलियत और उसूलों वाली विदेशी नीति ने हमें संतुलित और जिम्मेदारी की आवाज बना दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत ग्लोबल चर्चाओं के हाशिये पर नहीं खड़ा है,बल्कि हम उन्हें आकार दे रहे हैं। आजकल इंडो-पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के देश भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देखते हैं। यह भरोसा हमें अपने आप नहीं मिला है। यह देशों की संप्रभुता और नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर के हमारे लगातार सम्मान के जरिए कमाया गया है। भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, जिनमें आतंकवाद,कट्टरपंथी तत्वों को सीमा पार से सहयोग, मौजूदा हालात को बदलने की कोशिशें, समुद्री दबाव और यहां तक कि सूचना युद्ध भी। ये मुश्किल हालात हैं, जिनके लिए लगातार सावधान रहने और मकसद साफ रखने की जरूरत होती है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि भारत ने हमेशा शांति और बातचीत में विश्वास किया है और हम इसी नजरिए पर कायम हैं। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि जब हमारी संप्रभुता और हमारे लोगों की सुरक्षा की बात आती है, तो हम कोई समझौता नहीं करते।

बिहार में कांग्रेस की करारी हार पर बोले...राहुल गांधी-हम सब मिलकर लड़े थे,सब मिलकर हारे...

नई दिल्ली,28 नवम्बर 2025। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में बिहार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और हारे हुए उम्मीदवारों के साथ करीब चार घंटे लंबी मैराथन समीक्षा बैठक की। बैठक में राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हार की जिम्मेदारी सिर्फ बिहार इकाई पर थोपना गलत होगा,वे खुद भी इस हार के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। राहुल ने कहा, हम सब मिलकर लड़े थे, हम सब मिलकर हारे हैं। हार की जिम्मेदारी मैं भी उतनी ही लेता हूं जितनी बिहार के हमारे साथी ले रहे हैं। अब पीछे मुड़कर देखने या एक-दूसरे पर आरोप लगाने का वक्त नहीं है। हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है और संगठन को और मजबूत करना है। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने हार का पूरा ठीकरा चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर फोड़ा। पार्टी का दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए बिहार में बड़े पैमाने पर कांग्रेस और महागठबंधन समर्थकों के लाखों वोट जानबूझकर डिलीट कर दिए गए, जबकि फर्जी वोटर जोड़े गए।

क्या बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में मान्य है आधार कार्ड? इन राज्यों की सरकारों ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली,28 नवम्बर 2025। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आधार कार्ड जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोनों राज्यों ने इस बारे में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं।

आधार क्यों मान्य नहीं होगा : सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि किसी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर तय नहीं होती। यही वजह है कि इसे आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यूआईडीएआई ने भी स्पष्ट किया है कि आधार बनवाते समय जन्मतिथि साबित करने वाला कोई अनिवार्य दस्तावेज संलग्न नहीं होता।

यूपी सरकार ने क्या कहा : नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल के अनुसार नियुक्ति, प्रमोशन, सेवा रजिस्टर संशोधन या किसी संवेदनशील सरकारी प्रक्रिया में आधार को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में न माना जाए। इन जगहों पर जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट, नगर निकाय या स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण दस्तावेज ही मान्य होंगे। यह भी याद दिलाया गया कि आधार पहले भी नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं था।

महाराष्ट्र में क्या बदला : महाराष्ट्र सरकार ने भी आधार आधारित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने निर्देश दिया कि सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर जारी हुए सभी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र तुरंत रद्द किए जाएं। अगर कोई मामला संदिग्ध हो तो पुलिस में शिकायत दर्ज हो। सरकार का कहना है कि जाली दस्तावेजों के बढ़ते मामलों के कारण यह कदम जरूरी था। 11 अगस्त 2023 के संशोधन के बाद नायब तहसीलदारों द्वारा जारी ऐसे सभी प्रमाणपत्र अमान्य माने जाएंगे। केंद्रीय दिशा निर्देशों के मुताबिक भी आधार को जन्म या जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

संपादकीय

कर्नाटक कांग्रेस में लंबी चलेगी कुर्सी की लड़ाई

सीएम-डिप्टी सीएम में क्यों हो रही खींचतान

कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच खींचतान जारी है। ढाई साल के सीएम पद के वादे को लेकर दोनों नेताओं के समर्थक आमने-सामने हैं। यह जातिगत गुटबाजी पार्टी के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रही है, जिससे आलाकमान पर जल्द समाधान निकालने का दबाव बढ़ गया है।

कर्नाटक कांग्रेस का संकट लंबा खिंचता जा रहा है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में धीरे-धीरे दूसरे वरिष्ठ नेता भी शामिल हो गए हैं। यह टकराव जितना गहरा होगा, कांग्रेस के लिए मुश्किलें उतनी ही और बढ़ेंगी।

कर्नाटक की सियासत के केंद्र में इस समय एक वादा है। डीके शिवकुमार का कहना है कि 2023 में जीत के बाद उनसे कहा गया था कि ढाई साल बाद उन्हें सीएम बना दिया जाएगा। वहीं, सिद्धारमैया ढाई-ढाई साल के ऐसे किसी फॉर्मूले से इनकार कर रहे हैं। अब जब राज्य सरकार ने आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो कई विधायक दिल्ली जा डटे हैं, जबकि इधर बेंगलुरु में आपस में ही बयानबाजी चल रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी माना है कि कर्नाटक में सब ठीक नहीं चल रहा। हालांकि उन्हें भरोसा है कि वह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर मामले को सुलझा लेंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली में सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ पार्टी आलाकमान की बैठक हो सकती है। हालांकि किसी भी फैसले तक पहुंचना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। दोनों नेता अपने-अपने समुदायों के मजबूत चेहरे हैं।

डीके शिवकुमार राज्य में प्रभावी वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। अप्रैल में पेश जाति सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में इस समुदाय की आबादी 12.2त्न है। हालांकि समुदाय इस रिपोर्ट को गलत बताता है। वहीं, सिद्धारमैया ह्वष्ट की कुरुबा जाति से ताल्लुक रखते हैं। मौजूदा टकराव में दोनों तरफ से जातियों की गोलबंदी होने लगी है। वोक्कालिगारा संघ ने खुलकर शिवकुमार का समर्थन किया है। विधानसभा चुनाव के बाद ही कर्नाटक संकट के बीज पड़ गए थे और कई बार सीएम-डिप्टी सीएम के बीच का तनाव सार्वजनिक सतह पर दिखा। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व की तरफ से स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। संयोग है कि कांग्रेस ऐसी सिचुएशन में पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक कई बार फंस चुकी है। मध्य प्रदेश में इसी वजह से उसे सत्ता गंवानी पड़ी थी।

राज्य इकाइयों की गुटबाजी कांग्रेस को हमेशा से मुश्किल में डालती रही है, लेकिन लगता है कि पार्टी सबक लेने को तैयार नहीं है। हाल में बिहार विधानसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन से कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव है। इस बीच अगर कर्नाटक का मामला जल्द नहीं सुलझता,तो सवाल केवल स्टेट यूनिट नहीं, आलाकमान तक पर उठेंगे।

एसआईआर का विरोधःचिन्ता लोकतंत्र की या वोट बैंक की?

'' भारत का लोकतंत्र आज जिस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है,वहां उसकी विश्वसनीयता और मजबूती का सवाल पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गया है। चुनावों की पारदर्शिता, मतदाता सूची की शुचिता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मतदाता पहचान की सत्यता को बनाए रखना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं,बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को सुरक्षित रखने का मूल तत्व है। ''

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली-92

विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर इसी उद्देश्य से प्रारंभ की गई वह अनिवार्य प्रक्रिया है,जिसके माध्यम से मतदाता सूची में मौजूद संदिग्ध, दोहरे या अवैध प्रविष्टियों की पहचान और सत्यापन किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कार्य को लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक कदम माना जाना चाहिए, उसे कुछ विपक्षी दल अपने राजनीतिक हितों के चश्मे से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार के उतावले,भावनात्मक और अक्सर तथ्यहीन तर्क प्रस्तुत किए गए,उससे यही प्रतीत होता है कि यह विरोध किसी तर्क या सिद्धांत का नहीं, बल्कि वोट-बैंक की चिंता का परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर बेतूका राष्ट्र-विरोधही अे ंगा लगाने वालों को आईना ही दिखाया कि बिहार में तो एक भी व्यक्ति यह शिकायत करने नहीं आया कि उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार में एसआईआर के समय कुछ खास लोगों के वोट काटे जाने का आरोप उछालने वाले भी ऐसे कथित पीड़ित लोगों के उदाहरण का साक्ष्य नहीं दे सके थे। हालांकि बिहार में एसआईआर पर विपक्षी दलों को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन वे बाज नहीं आ रहे हैं और अब 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खे हैं।यह तब है,जब एसआईआर वाले राज्यों में करीब 65 प्रतिशत फार्म भरे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि लोग इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं। एसआईआर होना इसलिए आवश्यक है,क्योंकि मतदाता सूचियों में भारी त्रुटियां एवं विसंगतियां है,बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर जो अन्यत्र चले गए हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं, जिनके पास दोहरे मतदाता पहचान पत्र हैं। चुनाव आयोग एसआईआर के जरिये इन्हीं विसंगतियों को दूर कर रहा है,लेकिन विपक्षी दलों को पता नहीं क्यों यह रास नहीं आ रहा है। वे मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायत भी कर रहे हैं और एसआईआर भी नहीं होने देना चाहते है। लोकतंत्र की जड़ों में सबसे बड़ा विष तब घुलता है जब मतदाता सूची अवैध हस्तक्षेपों,बाहरी घुसपैठियों और राजनीतिक संरक्षण के सहारे खड़ी प्रविष्टियों से दूषित होने लगती है। भारत लंबे समय से विदेशी घुसपैठ की समस्या से

जूझ रहा है। राज्यों के बीच असंतुलित प्रवासन,सीमावर्ती क्षेत्रों में बेतरतीब आबादी का फैलाव, राजनीतिक शरण और संरक्षण के नाम पर अवैध बसेरों का निर्माण-ये सब ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्हें अनदेखा करना राष्ट्रहित से खिलवो है। एसआईआर की प्रक्रिया इसीलिए आरंभ की गई कि मतदाता सूची को अद्यतन,शुद्ध,विश्वसनीय, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित बनाया जा सके। यह प्रक्रिया किसी समुदाय, क्षेत्र या वर्ग के खिलाफ नहीं,बल्कि व्यक्तिगत पहचान के सत्यापन पर आधारित है। यह समान रूप से हर उस मतदाता की जांच करती है जो कानूनन इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बावजूद विपक्ष द्वारा इसे अधिकारों पर हमला, राजनीतिक भेदभाव या अविश्वास की राजनीति से जोड़ना केवल दुष्प्रचार एवं भोलेभाले लोगों को गुमराह करना है। यह सवाल इसलिए उठता है कि जब प्रक्रिया सबके लिए समान है, सभी क्षेत्रों पर लागू है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में संचालित हो रही है, तो किस आधार पर इसे लोकतंत्र विरोधी कहा जा सकता है? वास्तव में विपक्ष इस प्रश्न का ठोस, तथ्यपूर्ण उत्तर देने में असफल रहा है। यह आशंका निराधार नहीं कि बंगाल जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए मतदाता बन बैठे हैं। उनके बांग्लादेश लौटने से इसकी पुष्टि भी होती है। यह ठीक है कि पहचान पत्र के रूप में आधार भी मान्य है,लेकिन उसे भी फर्जी तरीके से बनवाया गया हो सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग को दस्तावेजों के सत्यापन का अधिकार मिलना ही चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत विपक्षी तर्कों का विश्लेषण करें, तो उनमें वास्तविक तथ्यों एवं आंकड़ों का अभाव है। भावनात्मक अपीलें, आशंकाओं का जानबूझकर सृजन, प्रशासनिक प्रक्रिया को अविश्वसनीय बताने का प्रयास, और तथ्यों से अधिक आरोपों का शोर-ये सब इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन को बचाना है। यदि मतदाता सूची वास्तव में त्रुटिरहित है, यदि घुसपैठियों का प्रश्न बिना आधार का है, यदि किसी वर्ग की वैधता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं,तो फिर सत्यापन से भय क्यों? सत्यापन तो वही व्यक्ति या समूह टालेगा, जो स्वयं को संदेह के घेरे में पाता हो। जो स्वच्छ, वैध और तथ्यपूर्ण हैं उन्हें कभी डर नहीं होता कि जांच उनके लिए समस्या बन जाएगी। इसलिए यह विरोध लोकतंत्र की चिंता नहीं बल्कि लोकतंत्र का उपयोग करके अपने हित साधने की कोशिश प्रतीत होता है। भारत की चुनाव प्रणाली में वर्षों से यह शिकायत उठती रही है कि मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियां, मृत व्यक्तियों के नाम, काल्पनिक मतदाता और बाहरी लोगों की अवैध प्रविष्टियां बे ती जा रही हैं। इनमें से अधिकांश समस्याएं प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसे राजनीतिक हितों का भी है जो ऐसी प्रविष्टियों को बनाए रखने में खुद को लाभान्वित देखते हैं।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि भारत के अनेक राज्यों में स्थानीय राजनीतिक तंत्र विदेशी घुसपैठियों के लिए न केवल छत्रछाया प्रदान करता रहा है, बल्कि उन्हें वोट-आधारित पहचान और सुविधाओं तक पहुंच भी दिलाता रहा है। इन परिस्थितियों में एसआईआर जैसी प्रक्रिया न केवल उचित है, बल्कि अत्यंत आवश्यक है। यह प्रक्रिया जितनी देर से लागू होगी, लोकतंत्र पर उतना ही खतरा बे गा। एसआईआर के विरोध का एक और पक्ष भी है, और वह है विपक्ष का यह डर कि यदि मतदाता सूची शुद्ध कर दी गई, तो उनका चुनावी गणित प्रभावित होगा। यह राजनीति का वह पक्ष है जिसमें आदर्शवाद के लिए बहुत कम जगह है। राजनीतिक दल अक्सर यह मानकर चलते हैं कि जहां संख्या उनके पक्ष में है,वहां सुधार का कोई हस्तक्षेप उनकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि नागरिक विश्वास और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षक है।

एसआईआर का उद्देश्य किसी को मताधिकार से वंचित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि मताधिकार का उपयोग वही करे जो इसके योग्य है, जो देश का वैध नागरिक है, और जिसका नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज है। भारत का भविष्य उन सुधारों पर निर्भर करता है जो चुनावों को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाएं। जब तक मतदाता सूची शुद्ध नहीं होगी,तब तक चुनाव परिणामों पर संदेह रहेगा और लोकतंत्र की साख कमजोर होती जाएगी। एसआईआर इस दिशा में उठाया गया साहसिक कदम है, जिसे किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव या भ्रम फैलाने वाले अभियानों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष और संरक्षित होती है, इसलिए विरोध के ये प्रयास और भी आधारहीन प्रतीत होते हैं।

बदलती विश्व-व्यवस्था और जी-20 की चुनौती : बहुध्रुवीयता के बीच भारत की उभरती वैश्विक भूमिका

भू-राजनीतिक तनावों,आर्थिक अस्थिरता और नेतृत्व संकट से जूझते जी-20 में भारत का वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में उदय

प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

जी-20 वैश्विक आर्थिक समन्वय का सबसे प्रभावी मंच है, परन्तु आज यह गहरे भू-राजनीतिक विभाजनों, महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा,आर्थिक असमानताओं और नेतृत्व संकट जैसी कई चुनौतियों से घिरा है। इससे समूह की प्रासंगिकता एवं क्षमता दोनों पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं। ऐसे जटिल समय में भारत ने स्वयं को वैश्विक दक्षिण की सशक्त आवाज़ के रूप में स्थापित किया है– अफ्रीकी संघ की सदस्यता सुनिश्चित करने से लेकर समावेशी विकास, शांति-आधारित कूटनीति और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के नए मॉडल प्रस्तुत करने तक। फिर भी वैश्विक शक्ति-संघर्ष भारत की प्रभाव क्षमता को सीमित करते हैं और जी-20 की कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं।

विश्व-राजनीति वर्तमान समय में गहरे परिवर्तनों से गुजर रही है। महाशक्तियों के बीच अविश्वास,क्षेत्रीययुद्ध, आर्थिक संकट, तकनीकी वर्चस्व की होड़, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे और वैश्विक संस्थाओं में घटती प्रभावशीलता ने विश्व-व्यवस्था को अस्थिर बना दिया है। ऐसे दौर में जी-20,जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का सबसे महत्त्वपूर्ण मंच है, स्वयं को अभूतपूर्व चुनौतियों के बीच पाता है। समूह की प्रभावशीलता पर बढ़ते संदेह मात्र इसके कार्य-तंत्र से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि यह बदलती विश्व-स्थिति और बहुध्रुवीयता के असंतुलन का प्रत्यक्ष परिणाम है।

जी-20 की सबसे गंभीर चुनौती गहराता हुआ भू-राजनीतिक विभाजन है। यूक्रेन क्षेत्र में चल रहा युद्ध, पश्चिम एशिया की अस्थिरता, प्रशांत क्षेत्र में टकराव, बड़े देशों के बीच तकनीकी एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तथा बढ़ते प्रतिबंधों ने समूह की सहमति-निर्माण क्षमता को कमजोर बनाया है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि साझा घोषणा-पत्र निकालना भी कठिन हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, जोहान्सबर्ग बैठक में केवल अत्यंत सामान्य रूप से 'स्थायी एवं न्यायपूर्ण शांति' की अपील की गई, क्योंकि सदस्य देशों के दृष्टिकोण आपस में टकराते रहे। यह स्थिति दिखाती है कि वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक स्वर तैयार करना कितना कठिन हो चुका है।

महाशक्तियों के व्यक्तिगत हित कई बार समूह के सामूहिक हितों पर भारी पड़ जाते हैं। इससे उबंटू–अर्थात् मैं हूँ क्योंकि हम हैं–जैसी साझी जिम्मेदारी की मूल भावना क्षीण होती जा रही है। कुछ प्रमुख देशों द्वारा सम्मेलन से दूरी बनाना, या महत्वपूर्ण विमर्शों में भागीदारी में अनिच्छा दिखाना, समूह की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। इससे जी-20 उस भूमिका को नहीं निभा पाता जिसके लिए यह बनाया गया था–यानी वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु सामूहिक एवं समन्वित प्रयास।

इसके साथ ही आर्थिक असमानता जी-20 के सामने एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। विकसित और विकासशील देशों के बीच आय, तकनीक,स्वास्थ्य-सुविधाएँ, कौशल, ऊर्जा स्त्रोतों और जलवायु वित्त में बढ़ती खाई ने समूह के भीतर संतुलन को प्रभावित किया है। वैश्विक ऋण संकट, विकासशील देशों पर बढ़ता आर्थिक दबाव, मंदी का खतरा, और असमान व्यापार-संरचना मिलकर ऐसे परिदृश्य का निर्माण करते हैं जिसमें साझा नीति बनाना कठिन हो जाता है। ऐसे समय में समूह को जिस सशक्त नेतृत्व और सहयोग की आवश्यकता है, वह कई बार अनुपस्थित दिखाई देता है।

इन जटिल परिस्थितियों के बीच भारत ने जी-20 में अत्यंत सकारात्मक, समावेशी और संतुलनकारी भूमिका निभाई है। भारत ने न केवल वैश्विक दक्षिण की चिंता और अपेक्षाओं को केंद्र में रखा, बल्कि ऐसे ठोस कदम भी उठाए जिनका दीर्घकालिक प्रभाव दिखाई देता है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि अफ्रीकी संघ को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाना रही। यह निर्णय न केवल ऐतिहासिक था, बल्कि उन विकासशील देशों की पुरानी मांग को भी पूरा करता था जिन्हें वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में बराबरी का स्थान नहीं मिलता रहा। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने विकासशील देशों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित कई व्यावहारिक एवं मापनीय पहलों को आगे बढ़ाया। डिजिटल सार्वजनिक संरचना का मॉडल, स्वास्थ्य-सुरक्षा व्यवस्था,कौशल विकास,ग्रामीण एवं कृषि नवाचार,मत्स्य प्रबंधन, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, आपदा प्रबंधन में सहयोग,और उपग्रह आँकड़ों का साझा उपयोग–ये सभी पहलें विकासशील देशों की आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हैं। विशेषकर अफ्रीका कौशल वृद्धि योजना जैसी पहलें लाखों युवाओं के लिए अवसरों का मार्ग खोलती हैं।

भारत ने वैश्विक सुरक्षा से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया, विशेषकर आतंकवाद और नशीली दवाओं के गठजोड़ को। यह विषय लंबे समय से वैश्विक विमर्श में अपेक्षित महत्व नहीं पाता रहा था। भारत ने इसके विरुद्ध कठोर और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु वित्त, सतत विकास, तकनीक की समान उपलब्धता और खाद्य-सुरक्षा जैसे विषयों पर भी भारत ने विकासशील देशों की सामूहिक आवाज़ को मजबूत किया।

क्या बीजेपी आगे बढ़ाएगी नीतीश की विरासत?

आलाकमान के इन फैसलों से मिल रहे संकेत

पूनम पाण्डे

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के साथ ही यह भी अहम है कि इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। दूसरे नंबर पर एनडीए है। जिस तरह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा

हुआ, उससे इस पर चर्चा होने लगी है कि क्या बिहार में सत्ता के समीकरण बदलेंगे और क्या बीजेपी ही नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाएगी।

गृह विभाग से कई संदेश

पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं है। बीजेपी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया है। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। चुनाव के दौरान जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन पर हत्या और गैंगरेप जैसे अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया गया, लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों की परवाह नहीं की। सम्राट चौधरी को टिकट ही नहीं दिया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके पक्ष में रैली भी की। प्रचंड जीत के बाद सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम पद के साथ-साथ गृह विभाग भी दे दिया गया।

इससे ये तो साफ है कि बीजेपी बिहार में स्थानीय नेतृत्व की नई खेप तैयार कर रही है। पहले बिहार बीजेपी के नेता के तौर पर सुशील मोदी का नाम ही सबकी जुबान पर आता था। अब बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को अपने बड़े नेता के तौर पर प्रॉजेक्ट कर रही है। कानून-व्यवस्था यहां चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था। गृह विभाग जितना अहम है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। यहां काम करने पर जितनी पब्लिसिटी मिल सकती है, वहीं कुछ गलत होने पर उतना ही दबाव और विरोध भी होता है।

सम्राट चौधरी के सामने अपनी पहचान बनाने की चुनौती है और मौका भी, जो बीजेपी ने उन्हें दिया है। इसकी शुरुआत भी सम्राट चौधरी ने की है। गृह विभाग संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संकेत दिए कि वे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्टाइल में बिहार की कानून-व्यवस्था को हैंडल करेंगे। बीजेपी ने साफ किया है कि बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के सुशासन की विरासत को ही आगे बढ़ाएगी। जब से नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई है तब से बीजेपी ने भी नीतीश के सुशासन की बात की है। जिस तरह का राजनीतिक समीकरण है, उससे ये लग रहा है कि नीतीश की विरासत को बीजेपी संभालने की कोशिश में है और जेडीयू इसमें धुंधली होती दिख रही है। हालांकि बीजेपी ने इसमें जल्दबाजी नहीं दिखाई है और वह सधे कदमों से ही इस ओर बढ़ रही है। गृह विभाग बीजेपी के पास होना इस दिशा में एक छोटा सा कदम है। कानून-व्यवस्था का मामला भले ही बीजेपीने अपने पास रखा है,लेकिन नीतीश कुमार के पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है तो ट्रांसफर-पोस्टिंग जैसी पावर उनके पास ही रहेगी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जिस तरह सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी दी कि उनके लिए बिहार में कोई जगह नहीं है,उसमें कहीं न कहीं यूपी के योगी है।

बेलगाम होती भाषाई अराजकता, सियासी नाकामी से उपजी कुंठा

उमेश चतुर्वेदी

इसे विडंबना ही कहेंगे कि जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और विकसित भारत की बातें हो रही हैं, तब देश के कुछ हिस्सों में भाषाई अराजकता बेलगाम हो रही है। मान्यता है कि शिक्षा और समृद्धि के साथ असमानता और संकीर्णता का भाव तिरोहित हो जाता है, लेकिन अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में जिस तरह भाषाई असहिष्णुता फैल रही है, उससे यह मान्यता गलत साबित होती दिख रही है। ताजा मामला महाराष्ट्र के कल्याण का है, जहां एक नौजवान ने इसलिए अपनी जीवनलीला खत्म कर ली, क्योंकि उसे हिंदी बोलने के लिए अपमानित किया गया। लोकल ट्रेन

से कालेज जाते वक्त सहयात्री से संवाद के लिए हिंदी के कुछ लफ्जों का इस्तेमाल कुछ मराठीभाषियों को इतना नागवार गुजरा, उन्होंने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इससे आहत नौजवान ने घर लौटकर आत्महत्या कर ली। यह नौजवान मराठीभाषी ही था।क्या हिंदी बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि किसी को सरेआम अपमानित किया जाए, पीटा जाए। इस आघातकारी मामले में राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की चुप्पी समस्या बनकर उभर रही है। ये संगठन भूल जाते हैं कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की हिंदी की क्षमता जिन लोगों ने पहचानी, उनमें गुजराती भाषी महात्मा गांधी एवं नर्मदाशंकर उपाध्याय, बांग्लाभाषी केशवचंद्र सेन एवं सुभाष चंद्र बोस और मराठा लोकमान्य तिलक जैसे अनेक अहिंदी भाषी थे। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनाने का सपना देखा था। राजनीतिक कुचक्रों के चलते हिंदी राष्ट्रभाषा के स्थान पर आसीन नहीं हो सकी, लेकिन उसकी सामर्थ्य किसी से छिपी नहीं। कई क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतें हिंदी से भयाक्रांत हैं, जबकि हिंदी के विस्तार के पीछे राजभाषा की ताकत नहीं, बल्कि उसका अभिव्यक्ति का सशक्त जरिया बनना है।

अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कदम

नए श्रम सुधार से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट

चार नई श्रम संहिताओं पर अमल समय की मांग को पूरी करने वाली एक बड़ी पहल है। इससे पहले की व्यवस्था में नियोक्ताओं को वेतन, कार्य स्थितियों और रोजगार श्रेणियों को असंगत तरीकों से परिभाषित करने वाले 29 अलग-अलग कानूनों का पालन करना पड़ता था। उनके स्थान पर नई संहिताओं में कानूनों को सुगम बनाया गया है। ये संहिताएं राज्यों में समान परिभाषाएं, सभी श्रमिकों के लिए लिखित नियुक्ति पत्र, समय पर वेतन भुगतान के लिए स्पष्ट नियम, गिग-प्लेटफार्म श्रमिकों की मान्यता,अद्यतन स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के साथ ही एक सरल राष्ट्रीय अनुपालन संरचना की रूपरेखा तैयार करती हैं।

पुरानी व्यवस्था में अस्पष्ट परिभाषाएं, सीमाओं में दखल और राज्यों के स्तर पर भिन्नताओं से कंपनियों को तमाम अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता था। किसी राज्य में प्रवेश से पहले कंपनी के समक्ष नए सिरे से अनुपालन की सिरदर्दी बढ़ जाती थी। इसके चलते विनिर्माण और लाजिस्टिक्स कंपनियों का विस्तार सीमित ही रहा। नई संहिताओं में अनिश्चितताओं को दूर किया गया है। स्पष्ट एवं एकसमान परिभाषाएं, पंजीकरण और रिटर्न की एकल प्रणाली, विस्तार के लिए नियामकीय परिदृश्य में सुसंगति इनके मूल में हैं। ये सुधार कारोबारी सुगमता बढ़ाते हैं। स्मरण रहे कि किसी देश की नियामकीय गुणवत्ता केवल सुधारों से ही नहीं, बल्कि नियमों के पूर्वानुमान से भी आंकी जाती है। जब कंपनियां कानूनी जटिलताओं से मुक्त होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं तो अनुपालन भी आसान एवं नियमित हो जाता है। तब निवेश निर्णय से लेकर सब्सिडी को लक्षित करना कही बेहतर हो जाता है। जोखिम घटने से काराबोरी परिवेश के प्रति भरोसा बढ़ता है।

आर्थिक दृष्टिकोण से यह परिवर्तन औपचारिक या संगठित रोजगारों को प्रोत्साहन देता है। नियुक्ति पत्र, स्पष्ट वेतन दायित्व और समन्वित श्रेणियां उन अनिश्चितताओं को दूर करती हैं, जो पहले अनौपचारिक रोजगारों को जारी रखने की गुंजाइश देती थीं। याद रहे कि रोजगारों की औपचारिक प्रवृत्ति उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायक बनती है। दस्तावेजीय अनुबंध और वेतन चक्र को लेकर सुनिश्चित होने से श्रमिक न केवल अधिक समय तक कार्य करने को लेकर तैयार रहते हैं, बल्कि नए कौशल सीखने के प्रति तत्पर होकर अपनी कुशलता बढ़ाने को भी प्रेरित होते हैं। अंततः इसका लाभ कंपनियों के लिए कार्यबल की क्षमताओं में सुधार और समग्र परिणामों में प्रत्यक्ष होता है। ये परिवर्तन भी किसी जबरन तरीके के बजाय संगठित एवं संस्थागत माध्यम से श्रम बाजार की दक्षता को बढ़ाते हैं।

-गौरव वल्लभ-

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

CMYK

जुआरियों ने छोड़ा सूरजपुर-मानी का जंगल,अब रामकोला-खोड़ जंगल में डेरा

पुलिस-साइबर की कथित सेटिंग फिर उजागर,संरक्षण के नए आरोप,पुराने चेहरे फिर सक्रिय

- शमशेर खान का 'फिर से जुआ फाड़' संचालित होने का फोटो मिला कथित रकम का पूरा चार्ट चौंकाने वाला
- हज से लौटा शमशेर खान...पर जुआ का 'तौबा' नहीं!
- कहता है जुआ नहीं चलाता,लेकिन 5-सदस्यीय टीम के साथ बड़ा 'जुआ फाड़' संचालित...पूरे जिले में सनसनी...
- टीम में बैकुंठपुर के पार्षद छोटे खान,विवेक पटेल,बबलू जायसवाल,रामकुमार जायसवाल सभी के नाम आए सामने
- खोड़-रामकोला जंगल में चल रहा करोड़ों का अवैध संचालन, पुलिस-साइबर की संदिग्ध चुप्पी

मानी में रोजाना 50 लाख का जुआ! चार महीने से चल रहा कथित खेल,पुलिस खामोश:सूत्र

'शिकायत करो, कुछ नहीं होगा,मानी में जुआ संचालित करने वालों का दावा? जांच की मांग तेज

जंगल में तंबू और तंबू के नीचे करोड़ों का जुआ...क्या पुलिस खुद संरक्षक? सूरजपुर के मानी जंगल में रोज़ करोड़ों का दांव!

सूरजपुर-उदयपुर की सीमा बनी अवैध जुआ का अड्डा...चार दिन में 1 करोड़ की कमाई–रामशेर गैंग का खुलासा

-शमरोज खान-

सूरजपुर 28 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।
हज बदला...दिल नहीं...जंगल बदला...जुआ नहीं...पुलिस बदली... संरक्षण नहीं, दैनिक घटती-घटना ने पहले भी मानी-उदयपुर बॉर्डर के जंगल में चल रहे करोड़ों के जुआ तंबू को उजागर किया था,उस खबर के बाद तंबू जरूर उखड़ा...लेकिन जुआ का खेल बंद नहीं हुआ, सिर्फ स्थान बदल गया है,अब जुआरी रामकोला के खोड़ जंगल में नया अड्डा बसाए बैठे हैं,और हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे फिर वही पुराने चेहरे, वही सेटिंग और वही संरक्षण का खेल सामने आ रहा है, जिले में अवैध जुआ नेटवर्क का सिरमौर माना जाने वाला शमशेर खान, हज यात्रा से लौटने के बाद यह जताता रहा कि उसने जुआ खेलना छोड़ दिया है...लेकिन जमीनी सच बिल्कुल उलटा है, दैनिक घटती-घटना की इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आए हैं, वे पूरे जिले के लिए चौंकाने वाले और हिला देने वाले हैं।

बता दे की दैनिक घटती-घटना ने कुछ सप्ताह पहले किया था दावा

मानी उदयपुर जंगल में चल रहे अवैध 'जुआ फाड़' का खुलासा किया था,खबर सामने आते ही पुलिस ने दबाव में आकर तंबू उखाड़ा,जुआरियों ने लोकेशन छोड़ी और इलाके में थोड़ी देर के लिए शांति लौटी,लेकिन अब सबकुछ बदल गया है जुआ का कारोबार नहीं रुका... बस जंगल बदल गया है, नई इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि जुआ सिंडिकेट ने अब अपना बड़ा अड्डा रामकोला-खोड़ जंगल में शिफ्ट कर लिया है और हैरानी की बात– इस पूरे ऑपरेशन को वही व्यक्ति संचालित कर रहा है जो हज से लौटा है और जिसने खुद सबके सामने कहा था 'जुआ हराम है।' दैनिक घटना इस पूरे नेटवर्क की अगली कड़ी में और नाम,और फोटो,और पैसों के लेन-देन का पूरा डेटा प्रकाशित करेगा,जुआ सिंडिकेट के तार कहाँ तक जुड़े हैं यह अगला बड़ा खुलासा होगा।

शमशेर खान फिर एक्टिव... 'जुआ फड़' का ताजा फोटो आया सामने

जारी का वही चर्चित चेहरा शमशेर खान,जो पहले भी मानी जंगल जुआ मामले में विवादों में था, अब खोड़ जंगल में फिर सक्रिय दिखाई दे रहा है,ताजा फोटो में वही व्यवस्था, वही तंबू,वही लेआउट साफ है कि जुआ नेटवर्क सिर्फ जंगल बदला है, संरक्षण वही है।

पिछली खबर पर कार्रवाई हुई थी...अब फिर वही खेल क्यों?

दैनिक घटती-घटना ने पहले मानी जंगल जुआ तंबू, जारी का नेटवर्क, संरक्षण से जुड़े आरोप जैसे गंभीर मुद्दे उजागर किए थे, पुलिस ने तब एक दबाव में कार्रवाई दिखाई भी थी, लेकिन अब फिर जगह बदली, सेटिंग वही, लोग वही, कमाई वही कहने को कार्रवाई हुई थी, लेकिन जुआ नेटवर्क आज भी उतना ही सुरक्षित है जितना पहले था।

सूत्रों के संगीन आरोप–पुलिस, साइबर टीम और जुआ संचालक के बीच पैसों का पूरा बंटवारा तय?-

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खोड़ जंगल में चल रहे इस अवैध जुआ घर में 7000 थाना प्रभारी, 5000 प्रतापपुर के एक अधिकारी को,18,000 गांव और आसपास के 'सेटिंग चैनल' में बांटा जाता वही 32,000 साइबर टीम के तीन लोगों को यह पूरा 'कलेक्शन चार्ट' जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साइबर टीम का एक आरक्षक,जुआरी शमशेर खान के घर से ही पैसा लाता है,यह आरोप प्रदेश स्तर तक हड़कंप मचाने के लिए काफी है।

जिले की एक बड़ी समस्या, अगर संरक्षण खत्म नहीं हुआ,तो जुआ का फैलाव बढ़ता जाएगा...

खोड़ जंगल का चयन भी बेहद सोच-समझकर किया गया है, घना इलाक़ा, सीमावर्ती रास्ते, पुलिस पेट्रोलिंग कम, रात में तेज भागने के कई मार्ग यानी 'आदर्श जुआ ज़ोन', जहाँ पुलिस की हर भनक पहले पहुंच जाती है।

प्रशासन से सवाल: क्या इस बार भी कार्रवाई सिर्फ दिखावा होगी?

- इस मुद्दे पर अब जिला प्रशासन को जवाब देना ही पड़ेगा...
- क्या आरोपों की जांच होगी?
- क्या साइबर टीम के संदेहास्पद रिश्ता की जांच होगी?
- क्या शमशेर खान जैसे लोगों पर रोक लगेगी?
- क्या जंगल-जंगल भाग रहा जुआ नेटवर्क खत्म होगा?
- अगर कार्रवाई नहीं हुई,तो इसका साफ मतलब होगा संरक्षण के बिना इतना बड़ा जुआ नेटवर्क चल ही नहीं सकता।'

जुआ का तंबू उखड़ा नहीं... सिर्फ पता बदल गया है...

मानी जंगल की रिपोर्टिंग के बाद, अब खोड़ जंगल का नया खुलासा, फिर वही कहानी दोहरा रहा है,अब सवाल पुलिस से बड़ा है जुआ रोकने की मंशा है या जुआ से मिलने वाली रकम का मोह? दैनिक घटती-घटना इस मामले की अगली कड़ी में फिर नए प्रमाण,नए चेहरे और नए तथ्य सामने लाएगा।

शमशेर खान की 'पोस्ट-हज टीम'... पांच लोग, पाँच भूमिकाएँ,एक बड़ा जुआ साम्राज्य

सूत्रों, स्थानीय ग्रामीणों और जुआ अड्डे के आसपास के विश्वसनीय स्रोतों ने पुष्टि की है कि शमशेर खान अब अकेला नहीं, बल्कि एक संगठित 5-मेंबर टीम के साथ काम कर रहा है। टीम के नाम सामने आए हैं–

1. छोटे खान - पार्षद,बैकुंठपुर नगर पालिका
शमशेर का नजदीकी, इलाके में 'प्रोटेक्शन सोशल कवर' देने का आरोप।

2. विवेक पटेल - फाइनेंशियल कॉलक्टर
जुआ घर से होने वाली दैनिक रकम का हिसाब-किताब संभालता है।

3. बबलू जायसवाल - सप्लाई एवं लॉजिस्टिक मैनेजर
टेंट, लाइट, कुर्सी, गाड़ियों की आवक-जावक नियंत्रित करता है।

4. रामकुमार जायसवाल - खिलाड़ियों को सेट करवाने का काम
जिले और बाहर के 'बड़े खिलाड़ियों' को बुलाने में सक्रिय।

5. जारी शमशेर खान - मास्टर ऑपरेटर
जुआ टेबल,रकम का अंतिम 'बांट', और पुलिस-साइबर से 'कोऑर्डिनेशन' संभालता है।

यानी जुआ अब केवल एक खेल नहीं—बल्कि एक संगठित, प्रशिक्षित, सुव्यवस्थित रैकेट बन चुका है।

थाना चौकियो मे सरगुजा पुलिस का साझा जनरेल परेड जवानों को अनुशासित रखने एसएसपी के सख्त निर्देश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा निर्देशन मे रक्षित केंद्र अंबिकापुर एवं विभिन्न थाना चौकियो मे ली गई जनरल परेड

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे जवानों को अनुशासित रखने, कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने एवं जनता के प्रति नम्र व्यवहार रखने के क्रम मे प्रति सप्ताह रक्षित केंद्र अंबिकापुर एवं विभिन्न थाना/चौकियो मे जनरल परेड का आयोजन करने के दिशा निर्देश दिए गए है, इसी क्रम मे आज दिनांक को रक्षित केंद्र अंबिकापुर, सहित थाना लुन्ड्रा, थाना बतौली एवं थाना सीतापुर मे साझा जनरल परेड आयोजित किया गया,रक्षित केंद्र अंबिकापुर मे आयोजित जनरल परेड की सलामी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा ली गई, सलामी पश्चात परेड का बारिकी से निरीक्षण किया गया,जिसमे बेहतर टर्नआउट वाले अधिकारियो/कर्मचारियों को इनाम देकर प्रोत्साहित किया गया। निरीक्षण पश्चात अधिकारी/कर्मचारियों को टोलीवार कूच कराकर परेड कराया गया एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा वाहन शाखा का निरीक्षण करते हुए सभी शासकीय वाहनों की बारीकी से जांच कर वाहनों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के दिशा निर्देश दिए गए, तत्पश्चात पुलिस लाईन के शस्त्रागार व स्टोर शाखा का निरीक्षण कर आर्म्स एम्युनेशन के रख-रखाव एवं रिकार्ड का बेहतर तरीके से संधारण करने के निर्देश दिए। अधिकारी व जवानों की सुविधा के लिए खोले गए पुलिस कल्याण कैन्टीन एवं पुलिस बैंक का लाभ लेने अधिकारी/कर्मचारियों कों प्रोत्साहित किया गया।

प्रतापपुर जनपद में फेरबदल : अनिल कुमार तिवारी बने नए सीईओ,विवादों में घिरे डॉ. निपेंद्र सिंह मूल विभाग लौटे

-संवाददाता-
प्रतापपुर,28 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।
सूरजपुर जिले के प्रतापपुर जनपद में लंबे समय से चल रहे प्रशासनिक विवाद और पंचायत प्रतिनिधियों के आक्रोश के बीच शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। आदिम जाति विकास विभाग ने आदेश जारी करते हुए अनिल कुमार तिवारी को प्रतापपुर जनपद पंचायत का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। वहीं विवादों में घिरे प्रभारी सीईओ डॉ. निपेंद्र सिंह को उनके मूल विभाग, पशु चिकित्सा सेवाएं, सूरजपुर वापस भेज दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में अनिल कुमार तिवारी को फरसाबहार जनपद पंचायत (जशपुर) में पदस्थ किया गया था, लेकिन नवीन संशोधित आदेश में उन्हें प्रतापपुर में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी आदेश के दूसरे प्रावधान में डॉ. निपेंद्र सिंह को प्रतापपुर से हटाकर मूल विभाग में वापसी का निर्देश दिया गया है। प्रतापपुर जनपद में डॉ. निपेंद्र सिंह का कार्यकाल शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है। सीईओ का पदभार संभालते ही पंचायत जनप्रतिनिधि उनके विरोध में उतर आए थे। जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सरपंचों ने कई बार आरोप लगाया कि डॉ. सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया।

उनकी शिकायतों पर कार्रवाई न होने पर प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कलेक्टर से तत्काल हटाने की मांग की थी। इतना ही नहीं, विरोध बढ़ने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने जनपद का घेराव के साथ चक्काजाम करने तक की चेतावनी दी थी। बताया जाता है कि पूर्व कार्यकाल में भी सरपंच संघ उनके विरुद्ध आंदोलन कर चुका था। 14 अगस्त को शासन ने उनका स्थानांतरण कर स्थायी सीईओ जयगोविंद गुप्ता को प्रतापपुर भेजा था,लेकिन डॉ. सिंह ने एक माह तक अपना प्रभार नहीं सौंपा,जिससे पंचायतों का कामकाज ठप होने लगा।

ऑनलाइन फ्रॉड पर बड़ा एक्शन,सूरजपुर पुलिस ने Facebook-Meta को थमाया नोटिस!

-संवाददाता-
सूरजपुर,28 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।
देश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए सूरजपुर पुलिस ने अब एक बहुत ही सख्त और निर्णायक कदम उठाया है। जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित साइबर अपराधों के तेजी से फैलते जाल को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही थी, लेकिन अब उसने पहली बार सोशल मीडिया दिग्गज Facebook की मूल कंपनी Meta को सीधे नोटिस जारी किया है। इस कदम को न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश में डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ

एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह पुलिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने का एक स्पष्ट संदेश है। यह कार्रवाई बताती है कि पुलिस अब केवल अपराधियों पर ही नहीं, बल्कि उस प्लेटफॉर्म पर भी नकेल कसने के मूड में है जिसका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा है।

नोटिस में पुलिस के कड़े सवाल : जारी किए गए नोटिस में सूरजपुर पुलिस ने Meta से कई स्पष्ट और कड़े सवाल पूछे हैं। पुलिस ने जानना चाहा है कि आखिर इस तरह के भ्रामक, आपत्तिजनक और अपराध को बढ़ावा देने वाले कंटेंट फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर कैसे और क्यों चल रहे हैं?

प्रदेशाध्यक्ष आए...सूरजपुर चूक गया...फिर वापसी में औपचारिक कार्यक्रम...सूरजपुर भाजपा में गुटबाजी खुलकर शुरू हो चुकी?

जिलाध्यक्ष-विधायक की बड़ी गलती,स्वागत न होने से फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा

प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत में हुई बड़ी चूक–वापसी में औपचारिक कार्यक्रम,गुटबाजी खुलकर सतह पर

वापसी में आयोजित कार्यक्रम रहा फीका...पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी, जिले में गुटबाजी की बू तेज...सूरजपुर भाजपा में संगीन असंतोष!

-शमरोज खान-

सूरजपुर, 28 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

सूरजपुर भाजपा की हालत पतली प्रदेशाध्यक्ष भी छूट गए,मनेंद्रगढ़ जाते समय स्वागत नहीं, लौटते समय शो-पीस कार्यक्रम,जिला संगठन चार लोगों की मुट्ठी में? महिला पदाधिकारी ने भी छोड़ी जिम्मेदारी,भाजपा में सूरजपुर मॉडलः स्वागत गायब,गुटबाजी हाज़िर, जिलाध्यक्ष-विधायक की 'डबल चूक' पर पूरे जिले में चर्चा,कार्यकर्ताओं में नाराज़गी चरम पर नए नेतृत्व की टीम विवादों में संगठन की टूट सतह पर दिखने लगी, भाजपा संगठन के लिए गुरुवार का दिन ऐसा रहा जिसने यह साफ कर दिया कि सूरजपुर जिले में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है, जब प्रदेशाध्यक्ष किरण देव, संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्री रामविचार नेताम,श्याम बिहारी जायसवाल सहित भारी-भरकम नेतृत्व मनेंद्रगढ़ कार्यालय भूमिपूजन के लिए अंबिकापुर से सड़क मार्ग से रवाना हुए,तो कोरिया जिले में उनका जोरदार स्वागत हुआ–लेकिन सूरजपुर में सन्नाटा रहा, यह दृश्य न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए शर्मनाक साबित हुआ, बल्कि यह भी स्पष्ट कर गया कि जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी और विधायक भूलन सिंह पूरा प्रबंधन ही चूक गए।

जिले में ही मौजूद थे जिलाध्यक्ष और विधायक,फिर भी स्वागत नहीं कार्यकर्ताओं में गहरी नाराज़गी

जिन जिलों में भाजपा का कारवां गुजरता है,वहाँ स्वागत एक परंपरागत संगठनात्मक संस्कृति मानी जाती है, लेकिन सूरजपुर में प्रदेश अध्यक्ष के पहले बड़े दौरे पर कोई स्वागत कार्यक्रम न होना, कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों तक में असंतोष का कारण बना रहा,कार्यकर्ताओं की सीधी टिप्पणी ऐसा सूरजपुर में पहली बार हुआ है।

वापसी में आनन-फानन में किया गया स्वागत...कार्यक्रम रहा फीका...

जब जिलाध्यक्ष को बात की गंभीरता का एहसास हुआ,तब मनेंद्रगढ़ से नेताओं की वापसी पर अग्रसेन चौक में जल्दी-जल्दी में एक कार्यक्रम तय किया गया,लेकिन कार्यक्रम में गिनती के कार्यकर्ता,ऊर्जा और जोश का अभाव,भारी नेतृत्व को मिला महज़ औपचारिक स्वागत यह सब अब जिलों की राजनीति में चर्चा का विषय है।

जिलाध्यक्ष पर गंभीर सवाल, क्या संगठन को चार लोगों की 'दरबारी टीम' चला रही है?

पार्टी के भीतरी हलकों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद,मुरली मनोहर सोनी की टीम पर,चार लोगों की मजबूत पकड़ हो चुकी है और यही लोग संगठन के दौरे, कार्यक्रम और जनसंपर्क पर नियंत्रण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का आरोप है की सरकारी कार्यक्रमों में जैकेट पहनकर रौब दिखाना आता है,लेकिन संगठन के काम में ज़मीन पर उतरना नहीं।

महिला मोर्चा में भी असंतोष,एक महीने में जिला पदाधिकारी ने छोड़ी जिम्मेदारी

संगठन के अंदर महिला कर्मियों में भी गहरा असंतोष है,एक चर्चित महिला पदाधिकारी ने जिले के संगठन में मात्र एक महीने के अंदर ही काम करने की अनिच्छा जताई, कार्यालय का फोन उठाना बंद किया,पार्टी की गतिविधियों से दूरी बना ली कारण पद बांटते समय संघर्ष करने वाली महिला नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और ऐसे लोगों को पद दे दिए गए जो विपक्ष के दिनों में सक्रिय भी नहीं थे, यह भाजपा के मजबूत महिला संगठनात्मक ढांचे के लिए गंभीर चेतावनी है।

क्या सूरजपुर भाजपा में गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है?

कुल मिलाकर स्थितियाँ संकेत देती हैं कि संगठन अप्रभावी नेतृत्व से ग्रस्त है, जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बढ़ रही है, नए जिलाध्यक्ष की पकड़ कमजोर है, विधायक और जिलाध्यक्ष की ट्यूनिंग सवालों के घेरे में है, संगठन में 'नए पावर सेंटर' पनप रहे हैं,यह सब सूरजपुर जैसी राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीट पर भाजपा के लिए ठोस खतरे की घंटी है।

प्रदेश नेतृत्व को तुरंत हस्तक्षेप करना होगा...

यह मामला अब सिर्फ 'स्वागत चूक' नहीं, जिला संगठन की टूटन का स्पष्ट संकेत है, अगर समय रहते समीक्षा नहीं हुई, गलत निर्णयों को नहीं सुधारा गया, कार्यकर्ताओं का सम्मान और विश्वास नहीं लौटा, तो सूरजपुर भाजपा आने वाले चुनावों में बड़ी चुनौती का सामना करेगी, और नुकसान तय है।

केजी-2 के छात्र को पेड़ से लटकाने वाले स्कूल की मान्यता रद्द हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान,संचालक पर भी एफआईआर

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नारायणपुर में स्थित हंसवाहिनी विद्या मंदिर की मान्यता डीईओ ने रद्द कर दी है। दरअसल केजी-2 में पढ़ने वाले छात्र द्वारा होमवर्क पूरा नहीं करने पर शिक्षिका ने उसे उसकी ही टी-शर्ट से पेड़ में लटका दिया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानकर स्वतः संज्ञान में लिया और शिक्षा सचिव ने शपथ पत्र पर जवाब मांगा था। इसके बाद स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की गई। शिक्षिका भी नाबालिग निकली है। रामानुजनगर के नारायणपुर स्थित प्राइवेट स्कूल हंसवाहिनी विद्या मंदिर में केजी-1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती थी। इसमें 60 बच्चे अध्ययनरत थे। 24 नवंबर को केजी-2 का एक छात्र होमवर्क नहीं कर पाया था।

इस पर वहां कार्यरत शिक्षिका ने उसे टी-शर्ट से पेड़ पर लटका दिया था। इस घटना का वीडियो पास के ही घर के एक युवक ने अपने मोबाइल में बनाकर वायरल कर दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था। वहीं मामले को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर संज्ञान में लिया। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की।

प्रभारी पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना/चौकी प्रभारी की ली गई अपराध समीक्षा बैठक

जिले की थाना/चौकीवार लंबित अपराधों,लंबित चालान,लंबित मर्ग, लंबित शिकायत एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर की की गई विस्तृत समीक्षा

-संवाददाता-

बलरामपुर,28 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

बलरामपुर प्रभारी पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले के समस्त राजपत्री अधिकारियों एवम् थाना/ चौकी प्रभारी की ली गई समीक्षा बैठक, बैठक के दौरान निर्देश देते हुए प्रभारियों को कहा कि वर्षात के पूर्व थाना चौकी में लंबित मामलों का अधिक से अधिक लक्ष्य को जल्द से जल्द निराकरण करें।

बैठक में फटकार लगाते हुए कहा...

प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने समीक्षा बैठक के दौरान पुराने लंबित प्रकरणों के विवेचको को फटकार लगाते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा निर्धारित कर जल्द से जल्द निराकरण करने कहा गया। जानकारी के अनुसार दिनांक 28/11/2025, दिन शुक्रवार को प्रभारी पुलिस अधीक्षक बलरामपुर मनोज कुमार खिलारी (भापुसे) द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर के सभागार कक्ष में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना चौकी प्रभारी की अपराध समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा के दौरान प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारी से थाना/चौकीवार लंबित अपराध, लंबित मर्ग, लंबित चालान,लंबित शिकायत की प्रत्येक प्रकारणवार विस्तृत समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक थाना चौकी प्रभारी से उनके थाने में लंबित मामलों का बारी-बारी से पूछताछ कर अत्यधिक दिनों से लंबित प्रकरणों में थाना प्रभारी/विवेचक को फटकार लगाते हुए समय सीमा निर्धारित कर शीघ्र प्रकरणों का निराकरण करने निर्देशित किया गया।

मीटिंग में एजेंडा वार कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा...

पुलिस अधीक्षक द्वारा मीटिंग में दिए गए एजेंडा वार थाना/चौकी के लंबित अपराध शिकायत मर्ग, लघु एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों का विश्लेषण कर थाना चौकी प्रभारी को वर्षात के मद्देनजर थानों के लंबित अपराध, शिकायतों का अधिक से अधिक निराकरण करने का लक्ष्य दिया गया।बैठक के दौरान प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया कि गिरफ्तारसुदा आरोपियों को समय पर न्यायालय पेश किया जावे, फिर भी अगर किसी कारणवश आरोपियों को हवालात में रखना पड़े तो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में त्वरित एवं कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देने की समझाइश दिया गया।

सुरंगपानी मिडिल स्कूल का प्रधान पाठक गणेश राम चौहान निलंबित

स्कूल की छात्राओं और महिला शिक्षिकाओं से अश्लीलता करने के आरोप पर जेडी सरगुजा की कार्रवाई,विभागीय जांच में आरोपों की हुई पुष्टि

-संवाददाता-

जशपुर,28 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कन्या सुरंगपानी के प्रधान पाठक गणेश राम चौहान को जांच प्रतिवेदन के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कन्या सुरंगपानी के प्रधान पाठक गणेश राम चौहान पर शराब के नशे में स्कूल आने और छात्राओं को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप विभागीय जांच में सही पाया गया है। संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कन्या सुरंगपानी के प्रधान पाठक गणेश राम चौहान के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच प्रतिवेदन में प्रधान पाठक पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। जांच के दौरान पाया गया कि, प्रधान पाठक गणेश राम चौहान शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होते थे। विभाग की जांच में अपने प्रधान पाटक पर स्कूल की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि, प्रधान पाठक गणेश राम चौहान, नशे की हालत में स्कूल आते थे और स्कूल की छात्राओं से अश्लील तरीके से बात करते थे और उन्हें मानसिक रूप से सब बच्चों के सामने प्रताड़ित करते थे। स्कूल की दो महिला शिक्षिकाओं ने भी प्रधान पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

व्यापार समाचार

रतन टाटा का सेशेल्स बीचफ्रंट विला बिकाऊ,85 लाख वाली प्रॉपर्टी के 55 करोड़ देने को तैयार है ग्राहक

नई दिल्ली, 28 नवम्बर 2025। सेशेल्स के माहे द्वीप पर स्थित रतन टाटा का खूबसूरत बीचफ्रंट विला एक बार फिर सुर्खियों में है। टाटा को यह संपत्ति इसलिए मिल सकी थी क्योंकि सेशेल्स सरकार ने उन्हें विशेष अनुमति दी थी, जबकि देश में आमतौर पर विदेशी नागरिकों को प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं होती। उस समय एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन ने इस विला की खरीद में रतन टाटा की मदद की थी। अब जानकारी सामने आई है कि शिवशंकरन और उनका परिवार या सहयोगी इस विला को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। विला की आधिकारिक वैल्यूएशन पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा लगभग 85 लाख रुपये आंकी गई है, लेकिन संभावित खरीदार इसे करीब 6.2 मिलियन डॉलर (लगभग 55 करोड़ रुपये) में खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। यदि यह सौदा पूरा होता है, तो बिक्री से प्राप्त राशि रतन टाटा एंडॉवमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडॉवमेंट ट्रस्ट के पास जाएगी।

उल्लेखनीय है कि रतन टाटा ने अपनी वसीयत में इस विला को अपनी निवेश फर्म आरएनटी एसोसिएट के नाम किया था, जो सिंगापुर में पंजीकृत है और भारत के कई उभरते स्टार्टअप्स में निवेश कर चुकी है। हालांकि, डील अभी फाइनल नहीं हुई है। जब शिवशंकरन से विला खरीदने की संभावित बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यह बयान संकेत देता है कि बातचीत भले चल रही हो, पर अभी समझौता पक्का नहीं हुआ है।

ग्राहक बनकर आए व्यक्ति ने किराना दुकान के गल्ले से 20 हजार रुपए चोरी कर हुआ फरार

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

सीतापुर में गुरुवार को ग्राहक बनकर आए व्यक्ति ने किराना दुकान के गल्ला से 20 हजार रुपए निकाल कर फरार हो गया। दुकान संचालक ने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रूपम गोयल सीतापुर का रहने वाला है। इसका सीतापुर में ही किराने की दुकान है। 26 नवंबर की दोपहर में एक अज्ञात व्यक्ति आया और लगभग 40 हजार का सामान लिस्ट तैयार करवाया। सामान को ले जाने के लिए पिकअप लेकर आया और लोड करवाने लगा। इस दौरान मौका पाकर दुकान के गल्ले से 20 हजार रुपए निकालकर फरार हो गया। सामान व पिकअप वहीं छोड़ दिया। दुकान संचालक ने पिकअप चालक से पूछा तो वह बताया कि किराए पर गायत्री मंदिर के पास से लेकर आया था और बतौली सामान छोडने की बात कही थी। दुकान संचालक रूपम गोयल ने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है।

लाल निशान पर बंद हुआ घरेलू शेयर बाजार,सेंसेक्स 13 अंक टूटा

नई दिल्ली,28 नवम्बर 2025। वृहद-आर्थिक आंकड़े आने के पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार उतार-चढ़ाव भरे वाले कारोबार में लाल निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसक्स 13.71 अंक यानी 0.016 फीसदी टूटकर 85,706.67 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसने 85,969.89 के ऊपरी और 85,577.82 अंक के निचले स्तर को छुआ। नेशनल स्टॉक एक्सेंचज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 12.60 अंक यानी 0.048 फीसदी गिरकर 26,202.95 के स्तर पर बंद हुआ है। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से पावर ग्रिड, इटर्नल, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस के शेयरों में सर्वाधिक गिरावट रही। वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा एशिया के अन्य शेयर बाजारों में शामिल दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग नीचे बंद हुए, जबकि जापान का निक्की और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक बढ़त में रहे। यूरोप के अधिकांश शेयर बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे।

एक दिन पहले गुरुवार को सेंसेक्स 110.88 अंक यानी 0.13 फीसदी उछलकर 85,720.38 अंक के स्तर पर बंद हुआ था। एनएसई का निफ्टी भी कारोबार के अंत में 10.25 अंक यानी 0.039 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 26,215.55 के स्तर पर बंद हुआ था।

जब पूर्व विधायक का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो जाए...

तो आम नागरिक का लोकतंत्र किसके भरोसे ?

भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो का नाम मतदाता सूची से कटा धरमजयगढ़ में हो गई मैपिंग,कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

प्रति
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय,
राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़
रायपुर (छ.ग.)

विषय – एस.आई.आर. (SIR) के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में तकनीकी त्रुटि के निराकरण हेतु आवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं गुलाब कमरों, निवासी – साल्ही, आपको यह निवेदन पत्र प्रेषित कर रहा/रही हूँ। एस.आई.आर. (SIR) प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने अपना फॉर्म संबंधित बी.एल.ओ. (BLO) के पास नियमानुसार जमा किया था। कुछ दिनों पश्चात बी.एल.ओ. द्वारा मुझे मौखिक रूप से सूचित किया गया कि मेरा नाम ऑनलाइन दर्ज नहीं हो पा रहा है। जब मैंने स्वयं अनेक बार ऑनलाइन करने का प्रयास किया, तब सिस्टम में लगातार एक अलर्ट संदेश प्रदर्शित हुआ, जिसमें उल्लेख था—

"This mapping has already been confirmed in the system by BLO Shanta Bai Mahant (9302620169) of State: Chhattisgarh, AC: 19-Dharamjaigarh, Part: 169-KAYA-1 against EPIC No.: LSC1058569"

इस संबंध में मैंने इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को भी मौखिक रूप से दी थी, किंतु आज दिनांक तक इस त्रुटि का निराकरण नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप मेरा एस.आई.आर. (SIR) फॉर्म ऑनलाइन सबमिट नहीं हो पा रहा है, जिससे मेरी निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया बाधित हो रही है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता/चाहती हूँ कि— वर्ष 2003 की मतदाता सूची में मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ क्रमांक 94—भल्लौर, के अनुभाग संख्या 7, पटेल पारा के सरल क्रमांक 767 में मेरा नाम विधिवत उल्लेखित है, जो कि ग्राम पंचायत साल्ही में आता है। मेरा पुराना EPIC नंबर MP/10/087/279026 है। वर्तमान मतदाता सूची में भी मेरा नाम ग्राम पंचायत साल्ही में ही दर्ज है, मै पूर्व में भरतपुर सोनहत विधानसभा से विधायक निर्वाचित हो चुका हूं, जो पुष्टि करता है कि मैं इसी विधानसभा क्षेत्र का/की नियमित मतदाता हूँ।

विधायक गुलाब कमरो ने इसे गम्भीर लापरवाही बताते हुए,मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा पत्र

कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एस आई आर में गंभीर लापरवाही का लगाया आरोप

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिये बनाया बड़ा मुद्दा

-राजन पाण्डेय-
एमसीबी, 28 नवंबर 2025
(घटती-घटना)।

भरतपुर-सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो का नाम मतदाता सूची से कटकर किसी दूसरे जिले धरमजयगढ़ में पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं है, यह सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं, बल्कि निर्वाचन प्रणाली में गहराई तक घुसी एक खतरनाक लापरवाही का प्रमाण है, और सबसे बड़ा प्रश्न यह क्या यह सिर्फ एक नाम का मामला है,या पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर खड़ा हुआ महा चुनौतीपूर्ण प्रश्न? बता दे की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाब कमरो का नाम मतदाता सूची से कटने की खबर कांग्रेस सोशल मीडिया हैंडल से वायरल है। इस खबर के वायरल होते ही लोग आश्चर्य चकित है और एस आई आर प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। खबर है कि गुलाब कमरो का नाम 2003 के सूची में भलोर बूथ क्रमांक 94 पर दर्ज है बावजूद इसके उनकी मैपिंग भरतपुर सोनहत विधानसभा के बूथ में न कर धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ में हो गई है और गृह ग्राम के बूथ में नाम शो नही हो रहा है।

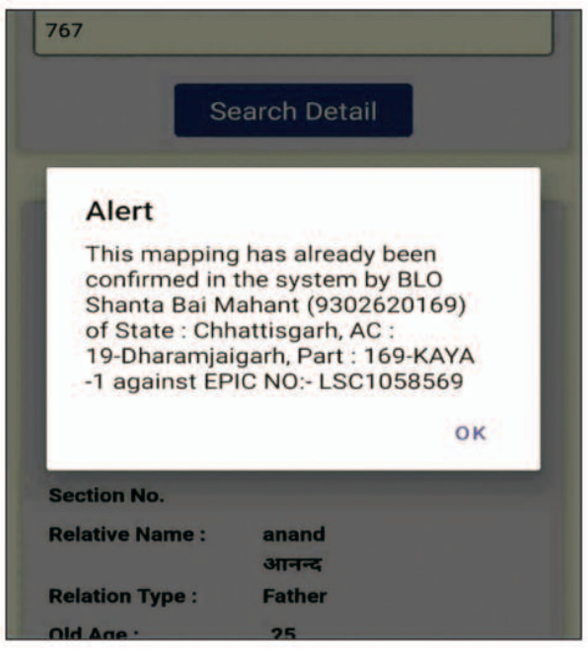

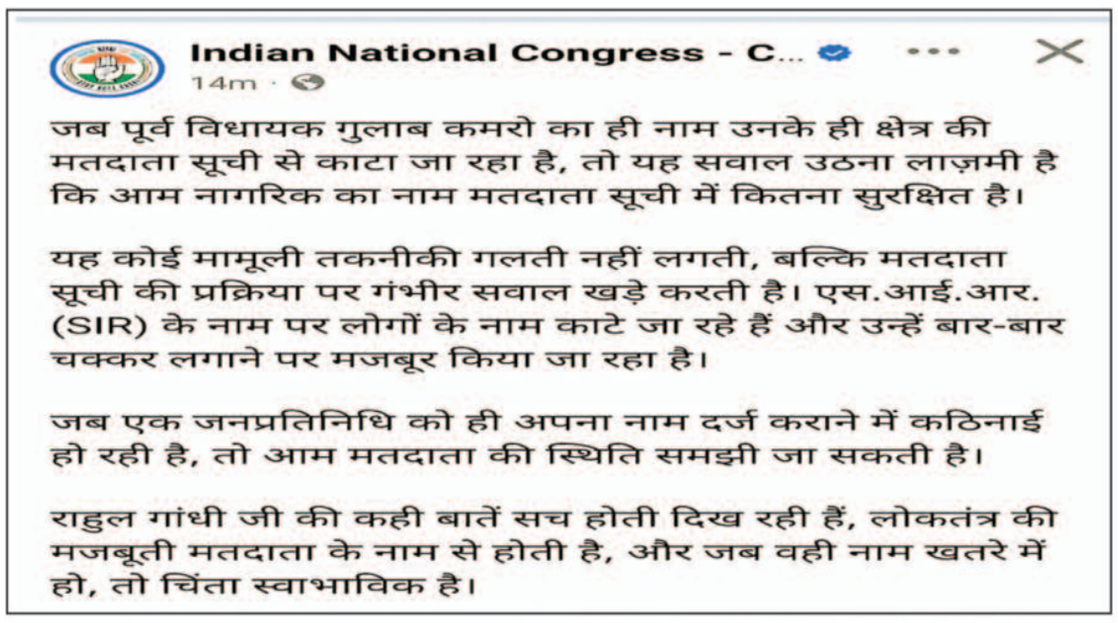

इस मामले पर इनके विचार...

जब मेरा नाम ही दूसरे जिले में मैप कर दिया गयाज सोचिए आम मतदाताओं के साथ क्या हो रहा होगा? यह गलती नहीं, चुनावी व्यवस्था की गंभीर लापरवाही है, एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची को सुव्यवस्थित करने के लिए है, लेकिन यहां नाम काटने और परेशान करने का माध्यम बनती जा रही है।
गुलाब कमरो,पूर्व विधायक

जब पूर्व विधायक का नाम ही कट जाए, तो आदिवासी और आम नागरिकों के नाम कितने सुरक्षित हैं–यह बड़ा सवाल है,नाम काटे जा रहे हैंज नाम गायब किए जा रहे हैंज्और यह सब 'तकनीकी त्रुटि' कहकर खारिज किया जा रहा है–यह स्वीकार्य नहीं।
सचिन पायलट,प्रभारी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस

मतदाता सूची से नाम हटाना कोई तकनीकी गलती नहीं,यह निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल है।
डॉ. चरण दास महंत,नेता प्रतिपक्ष

एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य सुधार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह भ्रम और अव्यवस्था का प्रतीक बन चुकी है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया सेल

राहुल गांधी की बात सही साबित हो रही है लोकतंत्र मतदाता के नाम से मजबूत होता है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस

मतदाता सूची अगर संदिग्ध होगी, तो चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता भी संदिग्ध होगी।
दैनिक घटती-घटना रवि सिंह

जब तीन बार विधायक रहे व्यक्ति का नाम ही 'शिफ्ट' हो जाए तो आम मतदाता किस भरोसे वोट डाले ?

गुलाब कमरो वह व्यक्ति हैं जो तीन बार चुनाव लड़ चुके,जिनकी राजनीतिक पहचान मजबूत है,जिनका नाम आज भी उनके गृह ग्राम साल्ही की सूची में दर्ज होना चाहिए,लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सामने आया संदेश धरमजयगढ़ के बीएलओ ने मैपिंग की पुष्टि कर दी है मतलब साफ है की जिस विधानसभा में व्यक्ति पैदा हुआ, बड़ा हुआ, राजनीति की,चुनाव लड़ा,उसका नाम किसी दूसरे जिले में दर्ज कर दिया गया,यह गलती नहीं यह सिस्टम में बैठी लापरवाही और जवाबदेही की कमी का भयानक उदाहरण है।

सवाल नंबर 1: यह एक गलती है या एक पैटर्न ?

जब सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जब विधायक का नाम कट सकता है तो आदिवासी और आम नागरिकों का क्या होगा? तो यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई है,क्योंकि हजारों लोग एसआईआर में लटक रहे हैं,बीएलओ से लेकर निर्वाचन कार्यालय तक जवाब नहीं दे रहे,लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं, सिस्टम 'एरर' दे रहा है, नाम कट रहे हैं,पर जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए चेतावनी है।

सवाल नंबर 2: चुनाव आयोग चुप क्यों ?

जब कांग्रेस पूछती है कि निर्वाचन आयोग से सवाल पूछो तो जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैंज्तो इससे आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है,मतदाता सूची किस पार्टी की संपत्ति नहीं,एक राष्ट्रीय संवैधानिक दस्तावेज है,और जब इसकी अद्यतन प्रक्रिया में ऐसे गंभीर 'मिसमैपिंग' सामने आए,तो चुप्पी किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं।

सवाल नंबर 3: क्या लोकतंत्र मतदाता के खिलाफ खड़ा हो रहा है ?

राहुल गांधी की यह बात आज बिल्कुल सटीक लग रही है लोकतंत्र की मजबूती मतदाता के नाम से होती है, अगर वही नाम गलत जिले में पहुँच जाए, बूथ से गायब हो जाए, ऑनलाइन दर्ज न हो पाए, सुधार के लिए महीनों दौड़ लगानी पड़े तो यह लोकतंत्र की मजबूती नहीं, लोकतंत्र की अस्थिरता का संकेत है।

मुख्य मुद्दा: यह गलती नहीं–प्रक्रिया की विफलता है...

पूर्व विधायक ने साफ कहा अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो जनता का क्या होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, आज एक प्रतिनिधि परेशान है, कल हजारों मतदाता बूथों पर खड़े होंगे और पाएंगे कि उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं यह लोकतांत्रिक अधिकार का सीधा हनन है।

अब जरूरत समाधान की,न कि सफाई की...

चुनाव आयोग को चाहिए पूरे प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा करे, हर विधानसभा में 'मिसमैच ऑडिट' कराए,गलत मैपिंग करने वाले कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई,15 दिन का विशेष सुधार अभियान जारी हो, नागरिकों को स्क्रू/सूचना देकर नाम पुष्टि की सुविधा मिले,क्योंकि अगर मतदाता सूची ही संदिग्ध होगी,तो चुनाव परिणामों पर सवाल खड़े होना तय है।

मतदान का अधिकार पवित्र है,और जब पवित्रता खतरे में हो, तो आवाज उठाना कर्तव्य है...

गुलाब कमरो का मामला एक चिंगारी है जो पूरे सिस्टम में छिपी खामियों की आग को दिखा रहा है, आज एक नाम गायब हुआ है, कल यह संख्या हजारोंङ्कलाखों में भी हो सकती है, अब फैसला आयोग को लेना है क्या वह इस गलती को सुधार बनाएगा, या इसे लोकतंत्र की नई आदत बनने देगा?

एनएच-43 पार करते ही मालगाड़ी से चौंके हाथी,उग्र होकर बुजुर्ग को दौड़ाकर कुचला

-संवाददाता-
कोरिया,28 नवंबर 2025
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगलों से भटककर हाथियों के झुंड अब आबादी वाले इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया है। इसी बीच गुरुवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 11 हाथियों के दल ने एक बुजुर्ग को दौड़ा-दौड़ाकर कुचल डाला। रेलवे ट्रैक के पास हाथियों ने बुजुर्ग को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर पैरों तले रौंदते हुए उसकी जान ले ली। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

मृतक की पहचान बांधपारा निवासी फुलसाय पंडो के रूप में हुई है। वह रेलवे ट्रैक के किनारे एक पेड़ के नीचे बनी झोपड़ी में अकेले रहते थे। फुलसाय का कोई परिवार नहीं था। उनके भाई समयलाल पंडो और भतीजे गांव में रहते हैं, जबकि फुलसाय लंबे समय से ट्रैक किनारे रहकर गुजर-बसर कर रहे थे। गुरुवार रात कटघोरा रेंज से 11 हाथियों का दल नेशनल हाईवे-43 को पार करते हुए बिशुनपुर की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार मालगाड़ी पटरियों से गुजरी। उसकी तेज आवाज और हॉर्न से हाथियों का झुंड डरकर बिखर गया और बेहद उग्र हो गया। बिखरा हुआ झुंड आगे बढ़ते हुए बांधपारा के पास पहुंचा, जहां फुलसाय पंडो की झोपड़ी थी।

हाथियों ने झोपड़ी तोड़ी,बुजुर्ग को सूंड से उठाकर पटक दिया- हाथियों ने फुलसाय की झोपड़ी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। शोर सुनकर जब फुलसाय झोपड़ी से बाहर भागे तो हाथियों ने उन्हें खदेड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन झुंड में शामिल हाथियों ने उन्हें सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कई बार पैरों से कुचल दिया। गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शव की हालत देखकर स्पष्ट था कि हाथियों ने बेरहमी से हमला किया था। हाथ-पैर टूट चुके थे और शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था।

सुबह ग्रामीणों ने देखा शव- सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक किनारे फुलसाय का शव पड़ा देखा और तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में बैकुंठपुर वन मंडल के डिप्टी रेंजर मंगल साय और चरचा थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय टीम के साथ मौके पर पहुंचे। क्षेत्र में हाथियों की सक्रियता को देखते हुए वन विभाग ने आसपास रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने और रात में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है।

परिजनों को दी गई तात्कालिक राहत राशि

रेंजर अजीत सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों को तत्काल राहत के रूप में 25 हजार रुपये प्रदान कर दिए गए हैं। इसके अलावा 5,75,000 रुपये की अंतिम क्षतिपूर्ति राशि हेतु प्रकरण तैयार कर लिया गया है। जांच और आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बाद यह राशि भी परिजनों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग,कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
जल संसाधन संभाग,कुनकुरी,जिला-जशपुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

eProcurement Portal:https://eproc.cgstate.gov.in

(प्रथम आमंत्रण)

निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 17.12. 2025 (17.30 बजे) तक ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है:-

सिस्टम निविदा क्र./ निविदा सूचना क्र./ दिनांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
सि.नि.क. 180420 नि.सु.क्र.03/वलेलि/2025-26 दिनांक-26-11-2025	केराकछार जलाशय योजना के नहरों में 8 नग संरचनाओं का निर्माण एवं पुनर्निर्माण, केनाल बैंक प्रोटेक्शन कार्य मुख्य तथा माईनर नहरों में सी. सी. लाईनिंग कार्य एवं मुख्य एवं शाखा नहरों को रिसेक्सनिंग दिनांक-26-11-2025 कार्य	रू. 550.97 लाख

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 17.12.2025, समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है।

नोट- 1. निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
2. निविदा की अनुमानित लागत एस.ओ.आर. 01.08.2010 (संशोधित 01.08.2022)

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.)
कृते मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार
जल संसाधन विभाग,अंबिकापुर (छ.ग.)

जी.नं.-252605087/6

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा0प्र0क्र0-.../ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक विशाल अग्रवाल आ0 राजेश अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर-2 पंजाब गाईन के पीछे, सुभाषनगर, भगवानपुर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के द्वारा शीट नम्बर -9 जेलपारा, नगर अम्बिकापुर 3511/6 रकबा 0.02,3/4 डिसमिल पर प्रस्तावित नक्शानुसार अनुसार भूतल पर रकबा 60.435 वर्गमीटर प्रथम तल पर रकबा 60.435 वर्गमीटर, द्वितीय तल पर रकबा 60.435 वर्गमीटर पर आवासीय भवन निर्माण कराने हेतु आवेदन पत्र मय मेन्टेनेन्स खसरा एवं प्रस्तावित ब्लूप्रिंट नक्शा की प्रति सहित आवेदन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा छ0ग0 में प्रस्तुत किया है जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय प्राप्त हुआ है ।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 17/12/2025 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा /आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक-26/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा0प्र0क्र0...

ईश्तहार

आगामी तिथि 04/12/2025

इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता / संस्था/विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक रमेश कुमार अग्रवाल आ0 त्रिलोक कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 72 वर्ष, व अन्य 2 निवासी मेन रोड सूरजपुर द्वारा नामांतरण करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि आवेदक के नाम से नगर सूरजपुर में नजूल भूमि प्लाट नम्बर 1987/2, 1991/2 रकबा 121, 243 वर्गमीटर कुल 2 प्लाट कुल रकबा 364 वर्गमीटर भूमि स्थित है। आवेदकगण के द्वारा पंजीकृत हक त्याग अनावेदक के पक्ष में कर दिया गया है। उक्त भूमि को अनावेदक के नाम पर नामांतरित किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना लेख कर नामांतरण आवेदक के नाम से किए जाने का अनुरोध किया गया है जो इस न्यायालय विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था / विभाग को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक/लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा / आपत्ति दिनांक 4/12/2025 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 19/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील
नजूल अधिकारी
सूरजपुर

क्या पटना के भ्रष्टाचार का अंत शुरू हो चुका है या यह सिर्फ पहला दरार है ?

पटना नगर पंचायत में बड़ा घोटाला उजागर... मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिकंदर सिदार निलंबित

विभागीय जांच में मिली अनियमितताओं की पुष्टि...अब होगी आगे कड़ी कार्यवाही...

दैनिक घटती-घटना की खबर का असर... आखिरकार हुई बड़ी कार्रवाई...

कई दिनों से लगातार प्रकाशित खुलासों ने हिलाया पूरा सिस्टम...

नगर पंचायत पटना में फैला भ्रष्टाचार अब विभाग कार्रवाई की मोड में...

निकाय निधि के पैसों में हुआ भारी भ्रष्टाचार...सरकार ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की...

क्या सरकार कार्रवाई कर रही है...या कार्रवाई होती दिखा रही है?

हमारी खबरों के बाद विभाग ने निलंबन का आदेश जारी किया...ठीक है,लेकिन यह शुरुआत है,अंत नहीं...

क्योंकि...

जो भुगतान फर्जी थे...उनकी रिकवरी कौन करेगा?

जिन कार्यों में अनियमितता हुई...उसका जिम्मेदार सिर्फ एक अधिकारी हैं या पूरा नेटवर्क?

जो राजनीतिक संरक्षण मिला...उसकी जांच कौन करेगा?

जो फाइलें गायब हुईं...उनका हिसाब कौन देगा?

अगर यह सब नहीं हुआ...तो आज की कार्रवाई महज़ 'पब्लिक साइलेंसर' बनकर रह जाएगी...

-रवि सिंह-

कोरिया/पटना,28 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

खबरें हमने लिखींऔर आखिरकार सच जीत गया...क्या पटना के भ्रष्टाचार का अंत शुरू हो चुका है या यह सिर्फ पहला दरार है? नगर पंचायत पटना की गड़बड़ियों पर महीनों से परत-दर-परत चढ़ाई गई चुप्पी को आखिरकार तोड़ने का श्रेय किसी सरकारी आदेश को नहीं, बल्कि लगातार उठाई गई हमारी पत्रकारिता की आवाज़ को जाता है, सरकार ने कार्रवाई की,यह स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल इससे बड़े हैं, क्योंकि अगर हर निलंबन सिर्फ एक डेटा एंट्री बनकर रह जाए तो यह राज्य की प्रशासनिक विश्वसनीयता पर सबसे गहरा सवाल है, सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि नगर पंचायत पटना में जो हुआ, वह कोई एक अधिकारी की गलती न थी और न है,यह पूरे सिस्टम की व्यवस्थित बीमारी है जहाँ नियम किताबों में हैं,पर फैसले 'सुविधा' देखकर लिए जाते हैं,नगर पंचायत पटना में निर्माण कार्यों के भुगतान से लेकर निकाय निधि के उपयोग तक फैल चुके भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आखिर सच साबित हो गए। छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सिकंदर सिदार को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उल्लंघन के तहत किया गया है, शासन के आदेश(File No.: GENS-11/4856/ 2025-D, दिनांक 26-11-2025) में स्पष्ट कहा गया है कि विभिन्न निर्माण कार्यों के भुगतान में गंभीर अनियमितताएँ,निकाय निधि के खर्च में नियमों को ताक पर रखा गया, जांच में तथ्य प्रमाणित पाए गए, जांच में यह साफ पाया गया कि नगर पंचायत पटना में कार्यों के निष्पादन के दौरान वित्तीय अनियमितताएँ,अनुचित भुगतान,और नियमों के विरुद्ध फैसले किए गए,जिससे निकाय को आर्थिक नुकसान पहुँचा।

बता दे की दैनिक घटती-घटना ने नगर पंचायत पटना की गड़बड़ियों पर सिर्फ एक खबर नहीं चलाई,लगातार, बार-बार,हर कोण से,हर दस्तावेज़ के साथ तथ्यों को सामने रखा, तभी जाकर सरकार को जागना पड़ा, जब सीएमओ छुट्टी पर थे हमने सवाल उठाया,जब छुट्टी से लौटे हमने सिस्टम को चुनौती देने वाली कार्यशैली उजागर की,जब निकाय निधि में खेल हुआ दस्तावेज़ों के साथ पूरा फाइल-ट्रेल छापा,जब भुगतान और निर्माण कार्यों में अनियमितता दिखी पूरा सबूत जनता के सामने रखा और अबज सरकार को कार्रवाई करनी ही पड़ी खबरों ने दबाव बनाया, नगर पंचायत पटना में चल रही मनमानी,बंदरबांट और सिस्टम को खुली चुनौती देने की शैली को लेकर दैनिक घटती-घटना ने जो अभियान चलाया था, वही आज सरकारी कार्रवाई का आधार बना,आपने पिछले दिनों पढ़ा हो की वही सीएमओ, जिनके लौटते ही फिर शुरू होगा वही खेल वाली हकीकत सामने आई,वही भ्रष्टाचार फाइल,जिसका भुगतान रिकॉर्ड हमने पेज-दर-पेज खोला,वही निरीक्षण में उड़ाई गई धूल, जिसे हमने प्वाइंट-बाय-प्वाइंट एक्सपोज़ किया, वही निकाय निधि का खेल, जिसे हमने प्रमाण के साथ पब्लिक में रखा, अब विभागीय कार्रवाई यह साबित करती है ÷जब पत्रकारिता सच्ची और सबूत आधारित हो, तो सिस्टम झुकता है। खबर का असर साफ है अब पटना के फाइलों पर ताले नहीं, जांच की मुहर लगेगी।

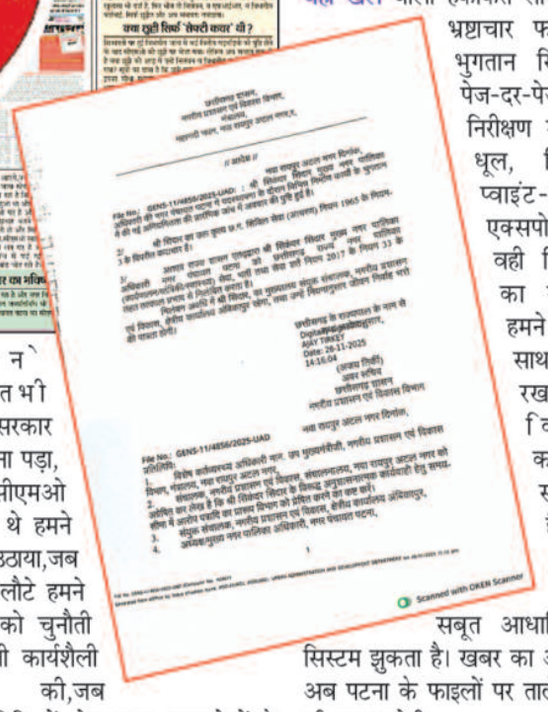

निलंबन के बाद सिदार को अंबिकापुर भेजा गया,मुख्यालय चिह्नित

आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में सिदार का मुख्यालय संयुक्त संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास,अंचल कार्यालय अंबिकापुर रहेगा,उन्हें शासनानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

सरकार की बड़ी कार्रवाई...भ्रष्टाचार पर जीरो-टॉलरेंस का संकेत

नगर पंचायत पटना में लंबे समय से निर्माण मद,खरीद मामलों और भुगतान प्रक्रिया को लेकर शिकायतें उठती रही थीं। विभागीय जांच के बाद सरकार की यह कार्रवाई कई सवालों के जवाब देती है क्या नगर पंचायत के ठेके और भुगतान एक तय सिंडिकेट की तरह चलते थे? क्या निकाय निधि को नियमविहीन तरीके से खर्च किया गया? क्या अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था? अब निलंबन के बाद यह मामला और बड़ा रूप लेने वाला है,क्योंकि विभाग ने आगे अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू करने के संकेत दिए हैं।

दैनिक घटती-घटना की रिपोर्टिंग फिर साबित हुई सही...

नगर पंचायत पटना में लगातार सामने लाई जा रही अनियमितताओं पर दैनिक घटती-घटना की रिपोर्ट पहले दिन से स्पष्ट थी,निकाय निधि में भारी खेल चल रहा है,निर्माण मद में अनियमित भुगतान हो रहे हैं और अधिकारी नियमों को धता बता रहे हैं, आज शासन के निलंबन आदेश ने उस पत्रकारिता को प्रमाणित कर दिया है।

भ्रष्टाचार सिर्फ फाइलों में नहीं होता भरोसे में भी होता है...

जब कोई अधिकारी छुट्टी के बाद लौटकर उसी अंदाज में काम शुरू कर देता है,जिस अंदाज में उसे रोकने के लिए जनता, मीडिया और विभाग तीनों संघर्ष कर रहे हों तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, व्यवस्था को खुलेआम दी गई चुनौती होती है, पटना नगर पंचायत में यही तो हुआ था और यही वह सच था, जिसे हमने पन्ने दर पन्ने उजागर किया।

पत्रकारिता जब प्रमाणों पर टिके तो सरकारें भी चुप नहीं रह सकतीं

दैनिक घटती-घटना ने जिन फाइलों के पन्ने दिखाएं, जिन कार्यों की जांच के दस्तावेज पब्लिश किए, जिन भुगतानों का हिसाब हमने टेबल पर रखा उन्हें नकारना सरकार के लिए भी संभव नहीं था, इसलिए आज की कार्रवाई का पूरा श्रेय जनता और पत्रकारिता दोनों को जाता है।

पत्रकार के विचार...असली लड़ाई अभी बाकी है...

निलंबन आदेश किसी भी बड़े भ्रष्टाचार में ट्रेलर होता है,फिल्म नहीं, अगर यह फाइल यहीं बंद हो गई तो यह न्याय नहीं, एक नई अन्याय की शुरुआत होगी,नगर पंचायत पटना में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो अधिकारी आज गिरा है,उसके पीछे खड़े लोग अभी भी सुरक्षित हैं, उनकी पहचान, उनका रोल और उनका शेयर अब इन्हें उजागर करना प्रशासन और सरकार की ज़िम्मेदारी है, अंत मेंज पत्रकारिता की जीत तभी कहलाएगी,जब जनता का पैसा जनता तक पहुँचे और नगर पंचायत पटना जैसी संस्थाएं व्यक्तिगत दुकानें नहीं, लोकतांत्रिक संस्थाएं बनकर काम करें,आज एक अधिकारी गिरे हैं कल व्यवस्था बदले,यही पत्रकारिता का लक्ष्य है और यही दैनिक घटती-घटना का वादा।

दैनिक घटती-घटना की जिम्मेदार पत्रकारिता...जनता की जीत

हमने न तो प्रेशर लिया...न धमकियों से घबराए...खबरों को न दबाया...न मोड़ा...और न ही किसी दबाव में फाइलें बंद कीं...अब सरकार की कार्रवाई से यह सिद्ध हो गया कि पत्रकारिता का असर होता है सच सामने रखा जाए तो दाल नहीं गलती...निकाय निधि के भ्रष्टाचार को छिपाने वाले अब बच नहीं पाएँगे

स.क्र.	पद	संख्या	वेतन
01	सह संपादक	1 पद	15,000
02	समाचार संपादक	1 पद	15,000
03	प्रबंध संपादक	1 पद	15,000
04	विज्ञापन प्रभारी	2 पद	10,000 से 15,000
05	ब्यूरो चीफ	1 पद	10,000 से 15,000
06	संवाददाता	2 पद	8000 से 12,000

नोटः- आवेदक फोन पर संपर्क ना करें।
स्वयं बायोडाटा के के साथ कार्यालय में संपर्क करें।
पता-कार्यालय दैनिक समाचार पत्र घटती-घटना
शनि मंदिर के पास, नमनाकला, अम्बिकापुर
छत्तीसगढ़, मो.नं. - 98265-32611

कलयुगी बेटे का खौफनाक कृत्यः पिता का सिर कुचलकर की हत्या

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,28 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पिता-पुत्र के रिश्ते को कलंकित कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां बड़े साल्ही चीतामाड़ा गांव में एक युवक ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर गुरुवार शाम न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पिता की लाश खेत में मिली

जानकारी के अनुसार, बचरापोड़ी चौकी क्षेत्र के ग्राम बड़े साल्ही चीतामाड़ा निवासी जगलाल रोज की तरह 24 नवंबर की रात अपने खेत में बने खलिहान में रखे धान की रखवाली करने गया था। अगली सुबह 25 नवंबर को स्थानीय लोगों ने खलिहान में उसकी खून से लथपथ लाश पड़ी देख पुलिस को सूचना दी। मृतक का सिर पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

पुलिस जांच में बेटे पर आया शक

घटना की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक जगलाल का बड़ा बेटा धर्मेंद्र सिंह अक्सर अपने पिता से विवाद करता था। गांव वालों ने बताया कि धर्मेंद्र नशे का आदी है और आए दिन पैसों की मांग करता रहता था। पिता द्वारा धान बेचने से रोकने और पैसे नहीं देने पर वह अक्सर झगड़ा करता था। कई बार उसने पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

पूछताछ में टूट गया आरोपी बेटा,कबूली हत्या

इन सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने धर्मेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी बेटे ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि पिता द्वारा धान बेचने से रोकने और पैसे देने से इंकार करने पर गुस्से में उसने खलिहान में रखे बड़े पत्थर से पिता का सिर कुचल दिया। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए उसने पत्थर को पास के कुएं में फेंक दिया।

वारदात में प्रयुक्त पत्थर बरामद

धर्मेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने कुएं से हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर बरामद कर लिया है। आरोपी को

गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है।

डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस...गाजीपुर थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवॉर्ड

अमित शाह ने 3 थानों को किया सम्मानित

रायपुर, 28 नवम्बर 2025। नवा रायपुर में IIM कैंपस में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के गाजीपुर थाना को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवॉर्ड मिला। अंडमान और निकोबार के पहरगांव पुलिस स्टेशन को दूसरा और कर्नाटक के रायचूर जिले के कवितला पुलिस स्टेशन को तीसरा स्थान मिला। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश के टॉप-3 पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया। थानों का चयन कुल 70 से ज्यादा कैटेगरी आधारित पैरामीटर्स पर किया गया। इस दौरान मंच पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल,रॉ चीफ पराग जैन और आईबी चीफ तपन डेका भी मौजूद रहे।

वहीं गाजीपुर थाना के प्रभारी यू. बाला शंकरन ने बताया कि मूल्यांकन में थानों की साफ-सफाई, जनता से व्यवहार, अपराध निपटान की गति, लंबित मामलों की स्थिति, साइबर और महिला सुरक्षा जैसे पैमानों को शामिल किया गया था। देश की इंटरनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस सिस्टम और भविष्य की स्ट्रेटेजी पर हाई-लेवल चर्चा हो रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी रात रायपुर पहुंचेंगे और कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री को नए स्पीकर हाउस एम-1 में ठहराया जाएगा, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वित्त मंत्री

एयरपोर्ट का अराइवल गेट 3 दिनों के लिए आम यात्रियों के लिए बंद

डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में देशभर से लगभग 600 अधिकारी और वीआईपी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस बार सम्मेलन में पहली बार एसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत माना एयरपोर्ट का अराइवल गेट तीन दिनों के लिए आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। यात्री गेट-2 का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, सम्मेलन के दौरान नया रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर भी प्रतिबंध है। डीजी-आईजी सम्मेलन के दौरान वीवीआईपी को आने-जाने में किसी तरह की रुकावट न हो, इसलिए नवा रायपुर क्षेत्र में मध्यम और भारी वाहनों की एंट्री बैन की गई है।

आवास एम-11 में ठहरे हैं। प्रधानमंत्री एम-1 और केंद्रीय गृहमंत्री एम-11 में ठहरेंगे। नए सर्किट हाउस में एनएसए अजीत डोभाल, डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह, आईबी चीफ तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव और दोनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ठहरने की व्यवस्था की गई है। सर्किट हाउस में 6 सूइट और 22 कमरे बुक किए गए हैं। ठाकुर प्यारेलाल संस्थान में 140 कमरे और निमोरा अकादमी में 91 कमरे बुक हैं। इस कार्यक्रम में 33 राज्यों से आने वाले डीजीपी, पैरामिलिट्री फोर्स के 20 डीजी/एडीजी समेत 75 पुलिस अधिकारी ठहरेंगे।

एडीजी और आईजी को सुरक्षा की कमान : डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य जिम्मेदारियां एडीजी दीपांशु काबरा और आईजी अमरेश मिश्रा को सौंपी गई हैं। राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय फोर्स, इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय (को-आर्डिनेशन) की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होगी। सभी अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आईजी छाबड़ा को भोजन व्यवस्था, ओपी पाल को आवास, ध्रुव गुप्ता को कंट्रोल रूम और अन्य अधिकारियों को परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है। वीआईपी जहां ठहरे हैं, वहां कमांडेंट या एसपी रैंक के अधिकारियों को सुरक्षा प्रभारी बनाया गया है। 3 शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

तोमर भाइयों ने सराफा व्यापारी को हनी-ट्रैप में फंसाकर डेढ़ करोड़ वसूले

रायपुर,28 नवम्बर 2025। सूदखोर वीरेंद्र और रोहित तोमर मामले में एक नया खुलासा हुआ है। तोमर भाई हनी ट्रैप गैंग भी ऑपरेट करते थे। पहले कारोबारियों की रेकी करवाते, फिर इस गैंग के सदस्य कारोबारियों से दोस्ती करते थे। इन्हें नशे की लत लगवाते और फिर हनी ट्रैप में फंसाते थे।

पंजाब विश्वविद्यालय परीक्षा सामग्री

होटलों और पब में ले-जाकर अश्लील वीडियो बनवाते और फिर यहीं से शुरू होता था इनका ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी और वसूली का काला धंधा। तोमर ब्रदर्स के हनी ट्रैप गैंग मामले में पड़ताल की है। यह इस पूरे मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है।

सराफा कारोबारी हनी ट्रैप का हुआ शिकार

पड़ताल के दौरान रायपुर के उस सराफा कारोबारी को ढूंढ निकाला,जो हनी ट्रैप का शिकार हुआ। इस शख्स ने वीरेंद्र-रोहित और उसके गुर्गों से माता-पिता, बीवी,भाई को बचाने अपना सबकुछ गंवा डाला। पहले इस कारोबारी से 5000 रुपए रोजाना वसूली शुरू हुई,जो 2 लाख रुपए प्रति दिन तक जा पहुंची। ऐसा करते-करते उसने एक साल में ही 5 लाख लोन का 1.5 करोड़ रुपए दे डाला। ऐसे एक नहीं, कई पीड़ित हैं लेकिन वे सिर्फ 2 वजह से पुलिस के सामने नहीं आ रहे। पहला- बदनामी। दूसरा- वीरेंद्र-रोहित छूटे तो उनसे जान का खतरा।

तोमर ब्रदर्स का भाठागांव में 10 करोड़ का घर : भाठागांव स्थित तोमर ब्रदर्स का घर, जो किसी आलीशान बंगले से कम नहीं है। आकलन है कि इस बंगले की कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस आने वाले समय में इसका भी

वेरिफिकेशन करवाएगी। क्योंकि बंगले की साज-सज्जा, इसमें इस्तेमाल फर्नीचर, पर्दे और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पेमेंट नहीं किया है।

रोहित तोमर अब भी फरार

- पांच महीने में आठ एफआईआर,17 मामले पहले से ही दर्ज हैं।
- वीरेंद्र तोमर- 163 दिन बाद 9 नवंबर को ग्वालियर से गिरफ्तार, जेल में।
- रोहित तोमर- 5 महीने से फरार।

पुलिस, राजस्व के अनुमान के मुताबिक सभी जमीनों की कीमत 20 करोड़ रुपए से अधिक है। उसने जिस समय खरीदी की, वो कलेक्टर गाइड-लाइन से कम दर पर की। उसमें भी गड़बड़ी की। इतना ही नहीं, पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उसने, परिवार के अलावा भी किन्हीं अन्य के नाम पर तो जमीनें नहीं खरीदीं।

डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस के बीच झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड ने किया सरेंडर 10 अन्य नक्सलियों ने भी डाले हथियार

रायपुर,28 नवम्बर 2025। नवा रायपुर में आज से शुरू हुए डीजीपी-आईजी कांफ्रेंस के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खूंखार नक्सली और झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड चैतू उर्फ़ श्याम ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि झीरम घाटी हमले में 30 कांग्रेस नेताओं की जान गई थी। चैतू उर्फ़ श्याम के साथ 10 अन्य साथी नक्सलियों ने एसपी सलभ कुमार के सामने आत्मसमर्पण किया। इससे पहले आज ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की सीपीआई-एम महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ जोन कमिटी की ओर से छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के नाम पत्र जारी कर एक जनवरी 2026 को सामूहिक आत्मसमर्पण की घोषणा की है। साथ ही यह मांग की गई है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को रोका जाए। पत्र में कहा गया कि नए वर्ष की पहली तारीख को कमेटी के सभी साथी एक साथ सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसके एक महीने पहले तीनों राज्यों की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे संयम बरतते हुए उक्त तारीख तक सुरक्षा बलों के अभियानों को पूरी तरह से रोक दें। जोन भर में कहीं भी गिरफ्तारी,मुठभेड़ ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को सुरक्षाबल अंजाम ना दें। पत्र में आगे कहा गया कि महीनेभर के दौरान हम जोनभर में बिखरे हमारे तमाम साथियों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा बलों के अभियान के जारी रहने से इसमें व्यवधान उत्पन्न होगा और फलस्वरूप प्रयास में तेजी नहीं ला पाएंगे। हम टुकड़ों-टुकड़ों में हथियार छोड़कर आने के बजाय एकसाथ या फिर कहे, एक बड़ी तादाद में सरकार के पुनर्वास योजना को स्वीकार करके मुख्यधारा में आना पसंद करेंगे।

कक्षा 6 से 8 तक स्किल एजुकेशन अनिवार्य 3 तरह के स्किल-बेस्ड प्रोजेक्ट होंगे जरूरी

रायपुर,28 नवम्बर 2025। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देशभर के सभी संबद्ध स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक स्किल एजुकेशन को अनिवार्य विषय के रूप में लागू कर दिया है। अब इन कक्षाओं के छात्र केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वास्तविक जीवन से जुड़े कौशल सीखेंगे। इसमें पौधों और पशुओं की देखभाल, बेसिक मैकेनिकल स्किल्स, मशीनों व सामग्री के साथ कार्य और ह्यूमन सर्विस से जुड़े प्रैक्टिकल शामिल हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्किल-बेस्ड एजुकेशन को अब मुख्यधारा की पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए 'स्किल बोध सीरीज' की नई किताबों को लागू करना अनिवार्य है, जो प्रिंट और डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होंगी। प्रत्येक वर्ष छात्रों को तीन कार्य-आधारित प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे। तीन वर्षों में कुल नौ प्रोजेक्ट्स और लगभग 270 घंटे का प्रैक्टिकल कार्य शामिल रहेगा। स्कूलों को अपने टाइमटेबल में बदलाव कर हर साल 110 घंटे स्किल एजुकेशन के लिए निर्धारित करने होंगे। प्रत्येक हफ्ते इस विषय के दो लगातार पीरियड अनिवार्य होंगे। प्रोजेक्ट चयन के लिए किताब में दिए छह विकल्पों में से स्कूल अपनी स्थानीय जरूरतों व संसाधनों के आधार पर तीन प्रोजेक्ट चुन सकेंगे। वहीं, शिक्षकों को भी नए कौशलों का प्रशिक्षण CBSE और NCERT संयुक्त रूप से देंगे। शैक्षणिक सत्र के अंत में स्कूलों में स्किल फेयर आयोजित होगा, जिसमें छात्र अपने मॉडल, प्रोजेक्ट और अनुभव प्रदर्शित करेंगे। मूल्यांकन में केवल 10 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के होंगे, जबकि बाकी वाइवा, प्रेजेंटेशन, गतिविधि पुस्तक, पोर्टफोलियो और शिक्षक अवलोकन पर आधारित होंगे।

एग्रोस्टेक पोर्टल में रकबा कटौती,अनावरी रिपोर्ट में पैदावार गायब!

किसानों का संकट चरम पर,मैदान में उबल रहा आक्रोश : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश

बिजली संकट, जमीन के दाम और मुआवजा—किसानों की तीन-तरफा लड़ाई... भाजपा नेताओं का घेराव तेज

रायपुर 28 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने इस समय त्रिस्तरीय संकट खड़ा है एग्रोस्टेक पोर्टल में धड़ाधड़ रकबा कटौती, अनावरी रिपोर्ट में पैदावार ही काट दी जा रही, बिजली और जमीन मूल्यांकन के विवाद अलग से आग भड़का रहे हैं, इन सबके बीच किसान संगठनों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, कई जगहों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और भाजपा नेतृत्व को सीधे निशाने पर ले लिया है, और कहा की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का घेराव - उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की भी घेराबंदी होगी राज्य में लगातार दौरे कर रहे भाजपा नेताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों

के तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा है,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में किसानों ने घेराव कर नारेबाजी की,उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को भी विरोध की गर्मी झेलनी पड़ी किसान 'रकबा कटौती बंद करो ', 'अनावरी में पैदावार क्यों काटी?' जैसे सवालों के साथ सड़कों पर उतर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान...अब भाजपा नेता गांवों में घुस नहीं पाएंगे- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा किसानों का रकबा काटा जा रहा है, पैदावार खत्म की जा रही है, बिजली संकट अलग...ये लड़ाई किसान लड़कर रहेंगे। अभी तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री का घेराव हुआ है,आगे कोई भी भाजपा नेता गांव-शहर नहीं घुस पाएगा,बघेल के इस बयान ने राज्य की सियासत में नई गर्मी ला दी है,कांग्रेस इसे 'किसान सम्मान की लड़ाई' बता रही है, जबकि भाजपा इसे 'भ्रम फैलाना' करार दे रही है, किसानों का दर्द जब खेत में बोया हमने, काट कौन रहा है? रकबा कटौती के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने आरोप लगाए हैं कि उनकी जमीन का एक हिस्सा पोर्टल से गायब है, फसल पैदावार आधी या शून्य दिखा दी गई है, बिजली कटौती ने सिंचाई ठप कर दी, जमीन मूल्य बढ़ने पर मुआवजे की लड़ाई अलग चल रही है, किसान कह रहे हैं कि प्रशासन सुन नहीं रहा, और नेताओं के दौरे सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित हैं।

मेमू ट्रेन हादसा : 23 दिन बाद सस्पेंड महिला पायलट का बयान,पर्दे की वजह से नहीं दिखी मालगाड़ी...

बिलासपुर, 28 नवम्बर 2025। गेवरा-बिलासपुर मेमू ट्रेन हादसे के 23 दिन बाद रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) बीके मिश्रा दोबारा बिलासपुर पहुँचे। उन्होंने 4 नवंबर को हुए हादसे में घायल और सस्पेंड असिस्टेंट लोको पायलट (एएलपी) रश्मि राज का अस्पताल जाकर करीब दो घंटे तक बयान लिया। हादसे के समय एएलपी रश्मि राज भी ट्रेन में सवार थीं और गंभीर रूप से घायल हुई थीं। उनका इलाज अब रेलवे अस्पताल में चल रहा है। सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि सीआरएस बीके मिश्रा ने रेलवे अस्पताल में सहायक लोको पायलट रश्मि राज का बयान लेने के बाद मंडल ऑफिस में कुछ अन्य अधिकारियों के भी बयान दर्ज किए हैं।

पहले ही हो चुकी है लापरवाही की पुष्टि : हादसे के बाद रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर ने भी रश्मि राज का बयान लिया था, जिसके आधार पर उन्हें सस्पेंड किया गया था। रश्मि राज ने अपने बयान में बताया था

कि हादसे से ठीक पहले सिग्नल 'यलो' था और स्टेशन मास्टर ने अगला सिग्नल 'ओके' होने की जानकारी दी थी। उनके मुताबिक, ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन लोको कैब में सामने लगा सनलाइट पर्दा अचानक गिर गया। जब वह पर्दा हटा रही थीं, तभी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी दिखी। उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी और मालगाड़ी से टकरा गई।

12 यात्रियों की हुई थी मौत..: यह भयानक हादसा 4 नवंबर को शाम 4 बजे के आसपास तब हुआ, जब तेज रफ्तार कोरबा पैसेंजर ट्रेन गतौरा रेलवे स्टेशन के लाल खदान के पास उसी रूट पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई।

एआई जीवन बना सकता है तो उसे बर्बाद भी सकता है : बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर,28 नवम्बर 2025। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अगर किसी की जिंदगी बना सकता है तो किसी को बर्बाद भी कर सकता है । नई पीढ़ी को इसका विशेष ध्यान रखना होगा यह बात सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल एआई कार्यशाला समापन समारोह में कही। गौरतलब है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 विधानसभाओं में पिछले दिनों विद्यार्थियों को निशुल्क एआई प्रशिक्षण दिया गया था। इसमें प्रति विधानसभा 300 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था, इसप्रकार पूरे लोकसभा क्षेत्र में 3000 विद्यार्थियो ने हिस्सा लिया । इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल पर बनाये गए गाने की लांचिंग की गई । जिसे कार्यशाला के दौरान बच्चों ने केवल 2 मिनट में बनाया था। कार्यशाला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

करने वाले विद्यार्थियों को सांसद द्वारा सम्मानित किया गया। देवेन्द्रनगर स्थित बालाजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में श्री अग्रवाल ने कहा कि नई पीढ़ी को एआई की अच्छाई के साथ बुराई भी बताना जरूरी है। एआई का उपयोग न केवल पढ़ाई बल्कि हम नेताओं को भी जरूरत पड़ने लगी है। हमें किसी विषय पर भाषण देना हो या कोई रेफरेंस देखना हो एआई के माध्यम से सेकेंड में मिल जाता है। स्कूली स्तर पर सभी बच्चों को ए आई की ट्रेनिंग अनिवार्य होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने खारिज की लैब टेक्नीशियन के लिए प्रमोशन नियम बदलने की मांग,कहा...कार्यपालिका के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं...

बिलासपुर,28 नवम्बर 2025। लैब टेक्नीशियन के एक समूह द्वारा दायर उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है,जिसमें राज्य सरकार को सेवा नियमों में संशोधन कर प्रमोशन का मार्ग बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने साफ कहा कि नए पदों का सृजन, नियमों में संशोधन या कैडर संरचना तय करना पूरी तरह कार्यपालिका का अधिकार है। अदालत इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों, खासतौर पर 2008 के अरावली गोल्फ क्लब केस का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि आर्थिक व प्रशासनिक प्रभाव वाले निर्णय न्यायालय नहीं ले सकता। अदालत ने कहा कि वह स्वयं को कार्यपालिका की भूमिका में नहीं ला सकती और न ही सरकार को पद सृजन या भर्ती नियम संशोधन के लिए मजबूर कर सकती है।

वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत हैं टेक्नीशियन

यह याचिका छह लैब टेक्नीशियन,जिनमें डॉ. ओम प्रकाश शर्मा भी शामिल हैं, की ओर से दायर की गई थी। वे कई सरकारी कॉलेजों में पिछले 22 से 40 वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत हैं। उनका तर्क था कि एमपी क्लास-तीन सर्विस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन (महाविद्यालय शाखा) नियम 1974 में लैब टेक्नीशियन के लिए कोई प्रमोशन का रास्ता नहीं है, जिससे वे पूरे करियर में एक ही पद पर अटके रहते हैं।

सरकार ने दी ये दलील : राज्य सरकार की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता एस.एस. बघेल ने दलील दी कि कैडर संरचना और नियम संशोधन कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं को 2001, 2009 और 2019 में समयमान वेतनमान के रूप में वित्तीय प्रगति दी गई है, जो करियर में ठहराव दूर करने का मान्य तरीका है। इसलिए उन्हें कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। कोर्ट ने राज्य की दलील पर सहमति जताते हुए कहा कि सिर्फ प्रमोशन न होने से याचिकाकर्ताओं को ऐसा कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता कि न्यायालय सरकार को सेवा नियम संशोधित करने का निर्देश दे। इस आधार पर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसे 1974 के नियमों में बदलाव कराने का कोई विधिक आधार नहीं है।

मतदाता सूची से विधायक का नाम ही कर दिया गायब,आम आदमी का क्या होगा : सचिन पायलट

जगदलपुर,28 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने एक प्रेस वार्ता में मतदाता सूची, निर्वाचन प्रक्रिया और राजनीतिक आरोपों से जुड़े मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं चरण दास महंत और पूर्व विधायक गुलाब सिंह कमरो के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। उनके अनुसार, जब एक विधायक का नाम सूची से हट सकता है, तो आदिवासी और आम नागरिकों के नाम भी प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाएगी। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने बताया कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाब सिंह

कमरो का नाम मतदाता सूची से हट गया था। उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ ने उन्हें सूचित किया कि उनका नाम सूची में नहीं है और बाद में ज्ञात हुआ कि नाम किसी अन्य गांव में स्थानांतरित कर दिया गया है। महंत ने कहा कि यदि एक विधायक के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह समझा जा सकता है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने विभिन्न स्थानों पर मतदाता सूची में नाम हटने से संबंधित शिकायतें उठाई हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग द्वारा जांच न करने से संदेह पैदा होता है। पायलट ने यह भी कहा कि जब निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं, और इसे उन्होंने आयोग की निष्पक्षता से जुड़े सवालों का कारण बताया। पायलट ने केंद्र सरकार से पिछले 11 वर्षों में भारत से बाहर भेजे गए घुसपैठियों के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की।

गृह विभाग का बड़ा आदेश : 36 अधिकारी लेवल-15 वेतनमान में नियुक्त

रायपुर,28 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ शासन ने गृह विभाग के महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत 36 अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह नियुक्ति विभागीय छानबीन समिति (डीपीसी) की 18 नवंबर 2025 को संपन्न बैठक में की गई अनुशंसाओं के आधार पर की गई है। शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 2-15/दो-गृह/रापुसे/2025 के मुताबिक, चयनित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (37,400-67,000, ग्रेड पे ?8,700 / वेतन मैट्रिक्स लेवल-15) का लाभ मिलेगा। सूची में दो अधिकारियों – ज्योति सिंह और रजत शर्मा – को 1 जनवरी 2024 से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिया गया है, जबकि शेष 34 अधिकारियों को यह लाभ 1 जनवरी 2025 से मिलेगा। शासन द्वारा जारी सूची में राजस्व, पुलिस, प्रशासन और अन्य विभागों से जुड़े अधिकारी शामिल हैं।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2023-2025-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)